वर्ष 12 • अंक 250 • 12 पृष्ठ
• मूल्य 5 रुपये
शनिवार 7 दिसंबर 2019
कोलकाता, चंडीगढ़, नई दिल्ली, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com

पृष्ठ 2

तुरंत नहीं मिलेगा शुल्क वृद्धि का लाभ

शशि करण शेट्टी पृष्ठ 3

एक्सप्रेस बिजनेस पर रहेगा ध्यान

डॉलर रु. 71.20 ▼ 10 पैसे | यूरो रु. 79.00 ▼ 10 पैसे | सोना (10ग्राम) रु 38022 ▼ 06.00 रुपये | सेंसेक्स 40455.10 ▼ 334.40 | निफ्टी 11921.50 ▼ 96.90 | निफ्टी फ्यूचर्स 11955.70 ▲ 34.20 | ब्रेंट क्रूड 64.00 डॉलर ▼ 0.20 डॉलर

एक नज़र

16 दिसंबर से चौबीसों घंटे एनईएफटी सेवा

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को कहा कि 16 दिसंबर से नैशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर (एनईएफटी) की सुविधा चौबीसों घंटे उपलब्ध होगी। मौजूदा समय में एनईएफटी भुगतान प्रणाली ग्राहकों के लिए सप्ताह के सभी कामकाजी दिनों (महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़कर) के दौरान सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक उपलब्ध है। आरबीआई ने सदस्य बैंकों को सलाह दी है कि यह भुगतान प्रणाली वर्ष के सभी दिन (अवकाश समेत) उपलब्ध होनी चाहिए।

मारुति ने बाजार से वापस मंगाई 63,493 कारें

देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजूकी इंडिया ने सियाज, अर्टिगा और एक्सएल6 मॉडल की कुल 63,493 कारें बाजार से वापस मंगवाई हैं। कंपनी को इन कारों में किसी खास तरह की कमी का पता चला है और उसे दूर करने के लिए इन्हें बाजार से वापस मंगाया गया है। कंपनी ने शुक्रवार को कहा कि कहा कि इन मॉडलों के पेट्रॉल स्मार्ट हाइब्रिड (एसएचवीएस) संस्करणों में मोटर जनरेटर इकाई (एमजीयू) में खामी होने की आशंका है। ये कारें 1 जनवरी 2019 से 21 नवंबर 2019 के बीच बनी हैं।

पुलिस मुठभेड़ में मरे हैदराबाद कांड के आरोपी

हैदराबाद में पशु-चिकित्सक के सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में गिरफ्तार किए गए चारों आरोपी शुक्रवार सुबह पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान दो पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। साइबराबाद पुलिस आयुक्त वीसी सज्जनर ने बताया कि जब गोलीबारी की घटना हुई तब आरोपियों के हाथों में हथकड़ी नहीं थी। उन्होंने कहा कि यह घटना सुबह पौने छह बजे से सवा छह बजे के बीच हुई। इस घटना पर मिली-जुली प्रतिक्रिया आई है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगेगी 30 हवाईअड्डों के लिए बोली

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि उड़ान योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र के 30 हवाईअड्डों और हवाई पट्टियों के लिए बोली मंगाई है। इनमें से छह हवाईअड्डों और हवाई पट्टियों से कम उड़ानें हैं जबकि 24 से कोई उड़ान नहीं है। इनमें असम के उमरंगसो रिजरवॉयर में वाटर एयरोड्रोम भी शामिल है। उड़ान के चौथे दौर की बोली 3 दिसंबर को शुरू हुई थी। इस सूची में अरुणाचल प्रदेश का पासीघाट और तेजू, असम का जोरहाट, रूपसी और तेजपुर तथा मेघालय का शिलॉंग हवाईअड्डा और हवाई पट्टी शामिल है।

सरकार ने मांगी ई-वाणिज्य कंपनियों से रिपोर्ट

सरकार ने एमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों के लिए हर साल 30 सितंबर तक एफडीआई नीति के अनुपालन से जुड़ी रिपोर्ट जमा करना अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में गुरुवार को जारी सरकारी अधिसूचना के अनुसार ई-वाणिज्य कंपनियों को पिछले वित्त वर्ष के लिए सितंबर अंत तक ऑडिटर की रिपोर्ट प्राप्त करनी होगी। विदेशी विनिमय प्रबंधन कानून (फेमा) की धारा 15 ई-वाणिज्य कंपनियों से संबद्ध है। अधिसूचना के अनुसार ई-वाणिज्य कंपनियों को रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि करनी होगी कि ई-वाणिज्य दिशानिर्देश का अनुपालन किया जा रहा है।

मदद नहीं तो कंपनी होगी बंद

मेघा मनचंदा और रोमिता मजूमदार
नई दिल्ली/मुंबई, 6 दिसंबर

वित्तीय संकट से जूझ रही दूरसंचार कंपनी वोडाफोन-आइडिया लिमिटेड के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला ने आज कहा कि अगर उनकी कंपनी को सरकार की तरफ से और राहत नहीं मिली तो वह बंद हो जाएगी।

बिड़ला ने हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में कहा, 'सरकार ने महसूस किया है कि यह एक अहम क्षेत्र है और पूरा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम इस पर टिका है। यह एक रणनीतिक क्षेत्र है। सरकार ने सार्वजनिक तौर पर कहा है कि वह निजी क्षेत्र की तीन और सरकारी क्षेत्र की एक कंपनी चाहती है। इसलिए हम सरकार से ज्यादा राहत की उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि यह इस क्षेत्र के अस्तित्व के लिए जरूरी है। यदि हमें कुछ नहीं मिलता है तो मेरा मानना है कि इससे वोडाफोन-आइडिया की कहानी का पटाक्षेप हो जाएगा।'

उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले वोडाफोन पीएलसी के मुख्य कार्याधिकारी निक रीड ने कहा था कि अगर केंद्र सरकार से राहत नहीं मिली तो कंपनी बिक जाएगी लेकिन बाद में वह अपने बयान से पलट गए थे। हाल में उच्चतम न्यायालय ने अपने एक आदेश में दूरसंचार कंपनियों के समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के मामले में सरकार की परिभाषा को सही ठहराया था। दूरसंचार कंपनियों को तीन महीने के भीतर 92 हजार करोड़ रुपये का बकाया चुकाना है।

वोडाफोन-आइडिया को सितंबर तिमाही में 36,959 करोड़ रुपये का कर पूर्व नुकसान हुआ था। इसमें एजीआर के लिए प्रावधान शामिल था। सितंबर तिमाही में कंपनी को 50,922 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड घाटा हुआ था। कंपनी ने लाइसेंस फीस के लिए 27,610 करोड़ रुपये और स्पेक्ट्रम उपयोगिता शुल्क के लिए 16,540 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था। इसमें 30 सितंबर, 2019 तक का ब्याज और इस पर जुर्माना शामिल है। इस तरह एजीआर के लिए उसे कुल 25,678 करोड़ रुपये का प्रावधान करना पड़ा।

इस तिमाही के दौरान कंपनी के उपभोक्ताओं की संख्या 90 लाख की गिरावट के साथ 31.11 करोड़ रह गई और प्रति ग्राहक औसत राजस्व भी एक रुपया घटकर 107 रुपये रह गया।

भारती एयरटेल, वोडाफोन-आइडिया और जियो ने हाल में अपनी सेवाओं की दर में बढ़ोतरी की है जिससे इस क्षेत्र को बहुत राहत मिली है। लेकिन वोडाफोन-आइडिया के पटरी पर लौटने को लेकर विश्लेषक अब भी आशंकित हैं। कंपनी का शेयर शुक्रवार को 5.3 फीसदी की गिरावट के साथ 6.92 रुपये पर बंद हुआ।

कर्ज का दर्द

- वोडाफोन आइडिया पर है 53,038 करोड़ रुपये की सांविधिक देनदारी
- सितंबर तिमाही में हुआ था कंपनी को रिकॉर्ड घाटा
- कंपनी पर कुल 1.17 लाख करोड़ रुपये का कर्ज

कुमार मंगलम बिड़ला
चेयरमैन, वोडाफोन आइडिया

कर्मचारी रहें निडर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दबाव से जूझ रहे बैंक कर्मचारियों को आश्वस्त करते हुए आज कहा कि उनके वैध कारोबारी फैसलों पर कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक उद्योग को लगता है कि उस पर दबाव है, लेकिन सरकार उसे निराश नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि बैंक कर्मचारियों के संरक्षण के लिए जल्दी ही एक व्यवस्था शुरू की जाएगी। मोदी ने 'हिंदुस्तान टाइम्स समिट' में कहा कि निचले आय वर्गों को कभी यह महसूस नहीं होना चाहिए कि उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा है। पृष्ठ 12

12 दिसंबर को आएंगे भारत बॉन्ड

इसके जरिये सार्वजनिक उपक्रम जुटाएंगे 15,000 करोड़ रुपये

अनूप रॉय और जश कृपलानी
मुंबई, 6 दिसंबर

- खुदरा निवेशकों की सुविधा के लिए सरकार पहले एएए रेटिंग वाले ईटीएफ से करेगी शुरुआत
- ईटीएफ में अधिक विविधता के प्रावधाव से जोखिम होगा कम
- विशेषज्ञों के अनुसार एकल बॉन्ड के मुकाबले ईटीएफ कर बचत के लिहाज से होगा बेहतर

भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) का निर्गम आगामी 12 दिसंबर को बाजार में दस्तक देगा। वित्त मंत्रालय के नजदीकी सूत्रों ने कहा कि इस ईटीएफ में शामिल सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां 15,000 करोड़ रुपये जुटाना चाह रही हैं। यह ईटीएफ दो सीरीज में बाजार में आएगा। तीन वर्ष की अवधि वाले ईटीएफ से 5,000 करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे, जिनमें 2,000 करोड़ रुपये का निर्गम आकार और 3,000 करोड़ रुपये का ग्रीन शू ऑप्शन (यूनिट आवंटन को लेकर विशेष प्रावधान) विकल्प शामिल होंगे। 10 वर्ष की सीरीज के लिए सार्वजनिक इकाइयां 10,000 करोड़ रुपये तक जुटा सकती हैं। इनमें 4,000 करोड़ रुपये निर्गम आकार और 6,000 करोड़ रुपये का ग्रीनशू ऑप्शन शामिल होगा।

शुरू में ईटीएफ में शामिल बॉन्ड को एएए-रेटिंग दी जाएगी, जिससे खुदरा निवेशकों का विश्वास जीतने और उन्हें आकर्षित करने में मदद मिलेगी। इस निर्गम के लिए सरकार ने निवेशकों को जागरूक करने के लिए भी बड़ा अभियान चला रखा है। सूत्र ने कहा इसका मकसद अधिक से धिक निवेशकों को एक बेहत सुरक्षित निर्गम में लाना है। सूत्रों ने कहा कि निवेशकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए एक फंड ऑफ फंड (एफओएफ) भी उतारा जाएगा, जिससे यह योजना केवल डीमैट खाताधारकों तक ही सीमित नहीं रह जाएगी। एफओएफ से निवेशकों को म्युचुअल फंड के जरिय ईटीएफ में निवेश का मौका मिलेगा। ईटीएफ निर्गम उतारने में सहयोग देने के लिए नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने निफ्टीभारत बॉन्ड इंडेक्स-अप्रैल 2023 और निफ्टीभारत बॉन्ड इंडेक्स-अप्रैल 2030 की शुरुआत की है। ये सूचकांक बॉन्ड के प्रदर्शन पर नजर रखेंगे।

उद्योग जगत के विशेषज्ञों के अनुसार अगर क्रियान्वयन के मोर्चे पर बाधा नहीं आई तो ईटीएफ आने के बाद फिक्सड इनकम बाजार में निवेशकों की दिलचस्पी दोबारा बहाल सकती है। एक विशेषज्ञ ने कहा, 'अगर यह योजना भारतीय डेट बाजार से जुड़े विभिन्न मुद्दों जैसे नकदी की खस्ता हालत, ऋण से जुड़े जोखिम आदि से निपटने में सक्षम रही तो फिर इसमें निवेश से जुड़ी काफी संभावनाएं होंगी।'

80,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त उधारी!

भारतीय रिजर्व बैंक के अस्थायी विराम ने बाजार को संकेत दे दिया है कि केंद्रीय बैंक को राजकोषीय घाटे का आंकड़ा लक्ष्य के पार निकल जाने का संदेह है और सरकार अतिरिक्त उधार ले सकती है। आरबीआई बजट के आंकड़ों की प्रतीक्षा कर रहा है। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए राजकोषीय घाटा 3.3 फीसदी के मुकाबले 3.6-3.7 फीसदी पर जा सकता है। पृष्ठ 2

बीपीसीएल के भरोसे आएगा विनिवेश लक्ष्य

अरूप रॉयचौधरी
नई दिल्ली, 6 दिसंबर

- सूत्रों के अनुसार एयर इंडिया के सौदे में हैं कई पेच, इस वित्त इसके विनिवेश की उम्मीद नहीं
- बीपीसीएल विनिवेश 31 मार्च तक हो सकता है पूरा
- सूत्रों के अनुसार बीपीसीएल सरकार के लिहाज से है आकर्षक सौदा
- अधिकारियों के अनुसार एयर इंडिया के बिना भी सरकार विनिवेश लक्ष्य कर सकती है हासिल

नरेंद्र मोदी सरकार को चालू वित्त वर्ष में एयर इंडिया की बिक्री के बगैर भी 1.05 लाख करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य हासिल कर लेने का भरोसा है। एयर इंडिया की रणनीतिक बिक्री के अगले वित्त वर्ष में ही पूरा हो पाने की स्थिति बन रही है। हालांकि उसे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) में हिस्सेदारी बिक्री की प्रक्रिया 31 मार्च तक पूरी हो जाने की उम्मीद है।

बिज़नेस स्टैंडर्ड को एक शीर्ष अधिकारी ने विनिवेश लक्ष्यों से जुड़ी प्रगति से अवगत कराते हुए यह जानकारी दी। इस अधिकारी ने कहा, 'एयर इंडिया के निजीकरण से जुड़ी जटिलताओं को देखते हुए और विमानन उद्योग की मौजूदा हालत में यह सौदा पूरा होने में वक्त लगेगा। ऐसे में यह सौदा इस वित्त वर्ष में पूरा नहीं हो पाएगा।'

वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एयर इंडिया की खरीद का अभिरुचि पत्र दिसंबर के अंत तक सामने आ जाएगा लेकिन सौदा पूरा होने में वक्त लगेगा। उन्होंने कहा, 'दूरसंचार क्षेत्र की तरह विमानन उद्योग भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है।' हालांकि सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनी बीपीसीएल की रणनीतिक बिक्री इस वित्त वर्ष के अंत तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। अधिकारी ने बीपीसीएल को खरीद के लिहाज से आकर्षक सौदा बताते हुए कहा, 'इसे अंजाम देना कहीं अधिक आसान होगा। इसे 31 मार्च 2020 के पहले पूरा किया जा सकता है।'

हालांकि इस अधिकारी ने भरोसा जताया है कि एयर इंडिया की बिक्री प्रक्रिया पूरी न होने पर भी इस साल का विनिवेश लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। वर्ष 2019-20 के बजट में विनिवेश के जरिये 1.05 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया था।

इसी क्रम में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गत महीने बीपीसीएल में अपनी समूची 53.29 फीसदी हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव पर सहमति जताई थी। हालांकि इस योजना से बीपीसीएल की नुमालीगढ़ रिफाइनरी को बाहर रखा गया है जिसमें उसकी 61.65 फीसदी हिस्सेदारी है।

सरकारी अधिकारियों एवं पेट्रोलियम क्षेत्र के विश्लेषकों का मानना है कि अपने सशक्त बुनियादी आधार एवं व्यापक नेटवर्क के बूते बीपीसीएल का हिस्सा 20-30 फीसदी प्रीमियम पर बेचा जा सकता है। तेल विपणन के अलावा शोधन, पाइपलाइन एवं पेट्रो-रसायन जैसे अन्य प्रमुख कारोबारों में भी बीपीसीएल की सक्रियता रही है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, पेट्रोनेट एवं ऑयल इंडिया में भी उसकी हिस्सेदारी है। बीपीसीएल की रणनीतिक खरीद में सऊदी अरामको, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टोटाल और एक्सॉन मोबिल के रुचि लेने की संभावना जताई जा रही है।

शुक्रवार को बंद बाजार भाव के मुताबिक बीपीसीएल में सरकार की हिस्सेदारी का मूल्य 56,000 करोड़ रुपये से भी अधिक है। अगर इस मूल्य पर करीब 30 फीसदी का प्रीमियम मिलता है तो सौदे के एवज में करीब 75,000 करोड़ रुपये सरकार के पास आ जाएंगे।

व्यापार गोष्ठी

कॉल दरों में इजाफा कितना जरूरी?

अपनी राय पासपोर्ट साइज फोटो और पूरे पते के साथ हमें इस पते पर भेजें :

बिज़नेस स्टैंडर्ड, नेहरू हाउस, 4 बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002 फैक्स नंबर - 011-23720201 या फिर ई-मेल करें goshthi@bsmail.in
अपने विचार आप हमें bshindi.com पर भी भेज सकते हैं

आज का सवाल

क्या सरकार को दूरसंचार कंपनियों से करनी चाहिए शुल्क वसूली

www.bshindi.com पर राय भेजें।
आप अपना जवाब एसएमएस भी कर सकते हैं। यदि आपका जवाब हां है तो BSP Y और यदि न है तो BSP N लिखकर 57007 पर भेजें।

पिछले सवाल का नतीजा

क्या रीपो दर को यथावत रखने का आरबीआई का निर्णय उचित है	
हां	75.00%
नहीं	25.00%

नेटफ्लिक्स का भारतीय सामग्री पर विशेष जोर

एजेंसियां
नई दिल्ली, 6 दिसंबर

नेटफ्लिक्स भारत में स्थानीय वास्तविक सामग्री पर अधिक जोर दिया है। कंपनी के संस्थापक एवं सीईओ रीड हास्टिंग्स ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने वर्ष 2019-20 में उन्होंने इस मकसद से 3,000 करोड़ रुपये निवेश किए हैं। हास्टिंग्स ने कहा कि कंपनी भारत में स्थानीय सामग्री पर विशेष जोर देने के लिए प्रतिबद्ध है और आने वाले महीनों में यह दिखने भी लगेगा। हास्टिंग्स ने यहां हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में ये बातें कहीं। उन्होंने कहा, 'हमने 2016 में शुरुआत की थी और इसके बाद लगातार निवेश कर रहे हैं। हमारे पास वैसी खासी सामग्री है, लेकिन हम यहां भारतीय लोगों की पसंद के अनुरूप सामग्री तैयार कर रहे हैं।'

बिजली वितरण के लिए आएगी 'आदित्य'

श्रेया जय
नई दिल्ली, 6 दिसंबर

- सरकारी बिजली वितरण कंपनियों के लिए नई सुधार योजना
- बुनियादी ढांचा बेहतर बनाने और स्मार्ट मीटरिंग पर जोर
- राज्यों को निजी साझेदार लाने के लिए मिलेगा प्रोत्साहन

देश में बिजली व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के लिए नई योजना पर 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इसका मकसद राज्यों में बिजली के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना, स्मार्ट मीटरिंग और आपूर्ति सुधारने के लिए निजी फ्रेंचाइजी मॉडल अपनाना है। यह योजना उदय की जगह लेगी जो मार्च 2020 में पूरी हो रही है। उदय में राज्यों को केंद्र की तरफ से सीधा अनुदान नहीं मिलता है।

सूत्रों के मुताबिक नई योजना का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर आदित्य यानी अटल डिस्ट्रिब्यूशन ट्रांसफॉर्मेशन योजना रखा जा सकता है। नई योजना के दो हिस्से हो सकते हैं। इनमें से एक बुनियादी ढांचे के लिए होगा जिसमें मौजूदा पारेषण और वितरण नेटवर्क का कायाकल्प करना, फीडर पृथक्करण, फीडर मीटरिंग और राज्य वितरण कंपनियों के कामकाज को सुगम बनाना शामिल है। इसमें राज्यों के लिए बिजली आपूर्तिकर्ताओं के रूप में कई निजी फ्रैंचाइजी को शामिल करने की योजना भी होगी। इसका दूसरा हिस्से में स्मार्ट मीटरों पर जोर होगा। इस योजना के दोनों हिस्सों के लिए खर्च की राशि बराबर बांटी जाएगी।

केंद्रीय बिजली मंत्री आर के सिंह के मुताबिक अगले तीन साल में पूरे देश में स्मार्ट मीटरिंग का काम पूरा हो जाएगा। सूत्रों का कहना है कि अनुदान में केंद्र का हिस्सा कुल खर्च का 40 से 60 फीसदी होगा। बाकी राशि राज्य सरकार वहन करेगी। एक अधिकारी ने कहा, 'यह सीधा-सीधा अनुदान नहीं है। केंद्र बिजली वितरण कंपनियों को सुधार के लिए प्रोत्साहन दे रहा है। हम चाहते हैं कि विभिन्न वित्तीय संस्थाएं आपस में हाथ मिलाएं और राज्यों में बिजली वितरण के सुधार में निवेश करें।' योजना के मसौदे के मुताबिक राज्यों के पास बिजली वितरण व्यवस्था को सुधारने के लिए मल्टीपल फ्रैंचाइजी मॉडल का विकल्प चुनने का अधिकार होगा। इसके तहत केंद्र 40 फीसदी लागत वहन करेगा। इसमें बिजली आपूर्ति के लिए निजी कंपनियों की सेवाएं लेनी होंगी। अगर राज्य अपने स्तर पर सुधार शुरू करते हैं तो केंद्र परियोजना के खर्च का 60 फीसदी हिस्सा वहन करेगा। अधिकारियों के मुताबिक अनुदान का आवंटन लक्ष्य आधारित होगा और यह ऋण के रूप में भी हो सकता है। एक अधिकारी ने कहा, 'प्रस्ताव को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इसके पीछे सोच वितरण कंपनियों को प्रोत्साहन देने की है, न कि उनके नुकसान की भरपाई करने की।'

डेलॉयट टच तोमात्सु इंडिया में पार्टनर देवाशिष मिश्रा ने कहा, 'कई राज्यों की वितरण कंपनियों के साथ समस्या यह है कि वहां बिजली की दरें लागत के मुताबिक नहीं हैं और उनके कामकाज में योजना के अनुसार सुधार नहीं हो रहा है। केंद्र की सहायता केवल पूंजी अनुदान के रूप में है और यही वजह है कि वितरण कंपनियां फिर वित्तीय संकट में फंस जाती हैं। इससे आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान में चूक होती है, परिचालन और मरम्मत पर कम खर्च किया जाता है और आपूर्ति की गुणवत्ता प्रभावित होती है।' सरकारी बिजली वितरण कंपनियों को पटरी पर लाने के लिए पिछले 15 साल में चार योजनाएं लाई गईं, लेकिन वे लगातार नुकसान में बनी रहीं।

संक्षेप में

गिरीश चंद्र चतुर्वेदी एनएसई के नए चेयरमैन नियुक्त

प्रमुख शेयर बाजार नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने जनहित निदेशक गिरीश चंद्र चतुर्वेदी को चेयरमैन नियुक्त किया है। एनएसई ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की मंजूरी के बाद यह नियुक्ति की गई है। यह पद अशोक चावला के जनवरी में एनएसई के चेयरमैन पद से इस्तीफे के बाद से खाली था। उनकी नियुक्ति शुक्रवार से प्रभाव में आ गई है। *भाषा*

बैंक ऑफ इंडिया की बोत्सवाना इकाई बंद

बैंक ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को कहा कि उसने बोत्सवाना में अपनी सहायक इकाई को बंद कर दिया है। बैंक ने बीएसई को बताया, यह सूचित किया जाता है कि पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक इकाई बैंक ऑफ इंडिया (बोत्सवाना) लिमिटेड का लाइसेंस पांच दिसंबर 2019 को नियामक को लौटा दिया गया। अत: इस सहायक इकाई को 5 दिसंबर से बंद माना जाए। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को विदेशी परिचालन दुरुस्त करने को कहा है। बैंक ने यह कदम इसी निर्देश के मद्देनजर उठाया है। *भाषा*

वाहन कलपुर्जा उद्योग का कारोबार 10 फीसदी घटा

वाहन कलपुर्जा उद्योग का कहना है कि उसका कुल कारोबार चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में 10 फीसदी से अधिक गिर गया है। यह उसके कुल कारोबार में सबसे बड़ी गिरावट है। वहीं उद्योग में जुलाई तक करीब एक लाख अस्थायी नौकरियां जा चुकी हैं। कलपुर्जा विनिर्माताओं के संगठन एक्मा ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में वाहन कलपुर्जा उद्योग ने कुल 1.79 लाख करोड़ रुपये का कारोबार किया। यह इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में उद्योग के कुल कारोबार 1.99 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले 10.1 फीसदी कम है। इस अवधि में कारोबार में नरमी का असर निवेश पर भी पड़ा है और उद्योग को 2 अरब डॉलर तक के निवेश का नुकसान उठाना पड़ा है। *भाषा*

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 9 पैसे मजबूत

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया शुक्रवार को 9 पैसे मजबूत होकर 71.20 रुपये प्रति डॉलर पर पहुंच गया। रिजर्व बैंक के नीतिगत दर में कोई बदलाव नहीं किए जाने तथा अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए नरम रुख बनाए रखने के निर्णय के एक दिन बाद रुपये में मजबूती आई। कारोबारियों के अनुसार रिजर्व बैंक की नरम रुख बनाए रखने की घोषणा से निवेशकों की धारणा मजबूत हुई। *भाषा*

जियो: तुरंत नहीं होगा वृद्धि का लाभ

जियो के मासिक प्लान की ओर आकर्षित हो सकते हैं कम एआरपीयू वाले ग्राहक

रोमिता मजूमदार
मुंबई, 6 दिसंबर

दूरसंचार विश्लेषकों को दिसंबर में दरों में नई वृद्धि से इस उद्योग की कंपनियों, खासकर जियो को वित्त वर्ष 2021 की पहली तिमाही तक ज्यादा लाभ मिलने की संभावना नहीं दिख रही है।

मौजूदा दर वृद्धि से पहले, 28-दिन की वैधता वाले प्लान दूरसंचार कंपनियों को अधिकतम प्रतिफल दिला रहे थे, क्योंकि लंबी अवधि के प्रीपेड प्लान 10 प्रतिशत से 45 प्रतिशत के दायरे में रियायती दर पर पेश किए जा रहे थे।

जेपी मॉर्गन में शोध विश्लेषक पिनाकिन पारेख ने लिखा है, 'जियो की नई दरें 6 दिसंबर से लागू हो गई हैं और इसलिए हमारी नजर में नए प्लान का पूरा लाभ मार्च तिमाही में स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है, लेकिन कंपनी को जून तिमाही से इसका लाभ मिलने लगेगा।' पारेख ने यह भी कहा है कि नए टैरिफ प्लान में जियो के मौजूदा ग्राहकों के 50 रुपये के वाउचर मान्य होंगे। इसके अलावा, दर वृद्धि की जानकारी फैलने से कई ग्राहकों द्वारा नियोजित वृद्धि से पहले रिचार्ज कराए जाने की संभावना है, जिससे दूरसंचार कंपनियों को अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में न्यूनतम लाभ मिलने का अनुमान है।

प्रीमियमः जियो बनाम एयरटेल

	पुराना	नया
2जीबी (28 दिन)	32 प्रतिशत	15 प्रतिशत
1.5 जीबी/	34 प्रतिशत	25 प्रतिशत
1.5 जीबी/	12 प्रतिशत	8 प्रतिशत
2 जीबी/दिन	11 प्रतिशत	17 प्रतिशत

प्रीमियमः जियो बनाम वोडाफोन आइडिया

	पुराना	नया
2जीबी	32 प्रतिशत	16 प्रतिशत
1.5 जीबी/	34 प्रतिशत	25 प्रतिशत
1.5 जीबी/	12 प्रतिशत	8 प्रतिशत
2 जीबी/दिन	14 प्रतिशत	17 प्रतिशत

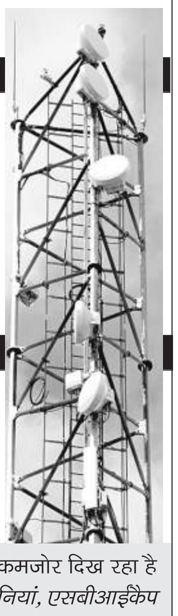

जियो की तुलना में भारती/वोडाफोन आइडिया का प्रीमियम कमजोर दिख रहा है
स्रोतः कंपनियां, एसबीआईकैप

हालांकि दूरसंचार कंपनियों द्वारा विभिन्न अवधि वाले प्लान के बारे में विस्तार से जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन दूसरी तिमाही के परिणाम के दौरान जियो के अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने ग्राहकों में लंबी अवधि वाले प्लान की लोकप्रियता में इजाफा देखा।

दूरसंचार ऑपरेटरों भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, दोनों ने अपने लोकप्रिय प्रीपेड प्लान के लिए लगभग 25 प्रतिशत की दर वृद्धि की घोषणा की है। इन दूरसंचार कंपनियों के प्रीपेड प्लान से उनके लगभग 60 प्रतिशत ग्राहक जुड़े हुए हैं। लेकिन न्यूनतम रिचार्ज प्लान (जिन्हें ग्राहकों को नंबर एक्टिव बनाए रखने के लिए जरूरत है) में 40 प्रतिशत तक का इजाफा दर्ज किया गया।

एसबीआईकैप सिक्योरिटीज के शोध प्रमुख राजीव शर्मा का कहना है, 'जियो ने अपने 28 दिन की वैधता वाले प्लान की दरें 12-14 प्रतिशत तक बढ़ाई हैं जिससे संकेत मिलता है कि कंपनी का ध्यान ग्राहकों को जोड़ने पर लगा हुआ है। सबसे ज्यादा दर वृद्धि (39 प्रतिशत) 84-दिन की श्रेणी में की गई है। जियो ने नया 56-दिन का प्लान भी पेश किया है जिसमें 28 दिन के प्लान की तुलना में ज्यादा वॉइस कॉलिंग लाभ की पेशकश की गई है।' हालांकि इस नई श्रेणी में ग्राहकों के लिए प्रति जीबी ज्यादा मूल्य चुकाना होगा जिससे पता चलता है कि जियो ने लंबे समय तक बड़ा डिस्काउंट देने की योजना नहीं बनाई है। इससे वित्त वर्ष 2021 तक उसके एआरपीयू में लगभग 29 प्रतिशत का इजाफा होगा और कंपनी को करीब 1.5 अरब डॉलर का एबिटा हासिल होगा।

इन दर वृद्धि से पहले जियो के 28-दिन की श्रेणी वाले प्लान प्रतिस्पर्धी दूरसंचार कंपनियों के मुकाबले 25 प्रतिशत सस्ती कीमत पर उपलब्ध थे, जबकि 84-दिन की वैधता वाले प्लान 10 प्रतिशत डिस्काउंट पर उपलब्ध थे। मौजूदा दर वृद्धि जियो के ग्राहकों में लोकप्रिय 84-दिन के प्लान की बजाय 28 दिन के प्लान का आकर्षण बढ़ सकता है।

अरबिंदो ने अमेरिकी बाजार से वापस मंगाई तीन दवा

बी दशरथ रेड्डी
हैदराबाद, 6 दिसंबर

प्रमुख औषधि कंपनी अरबिंदो फार्मा अमेरिकी बाजार से अपनी तीन दवाओं को वापस मंगाने की पहल की है। इनमें दो दवाओं को विनिर्माण कारणों से वापस मंगाया जा रहा है। कंपनी के कई विनिर्माण संयंत्र को अमेरिकी औषधि नियामक यूएसएफडीए के नियामकीय अनुपालन संबंधी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है और इस घटना को भी उसी संदर्भ में देखा जा रहा है।

वापस मंगाई जा रही दवाओं में रैनिटिडीन भी शामिल है जिसके लिए अमेरिकी औषधि नियामक ने हाल में बाजार से वापस मंगाने का निर्देश दिया था। रैनिटिडीन में खतरनाक तत्व एनडीएमए की मात्रा तय मात्रा से अधिक पाए जाने पर यूएसएफडीए ने यह निर्देश दिया था। यूएसएफडीए के अनुसार, रैनिटिडीन दवा के विभिन्न खुराक वाले टैबलेट एवं कैप्सूल के कुल करीब 2,76,048 बोतल को वापस मंगाया जा रहा है। इसके अलावा रैनिटिडीन सीरप के 19,320 बोतल को भी अमेरिकी बाजार से वापसी हो रही है। कंपनी ने स्वैच्छिक तौर पर एमियोडैरोन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन और स्थानीय एनोस्थेटिक लिडोकाइन एचसीएल इंजेक्शन के खास बैच के क्रमश: 1.97 लाख वाइल और 1.12 लाख वाइल को वापस मंगाया है। अमेरिकी बाजार में इन तीनों दवाओं का वितरण अरबिंदो फार्मा की अमेरिकी सहायक इकाई ऑरोमेडिक्स फार्मा एलएलसी द्वारा किया जाता है। अरबिंदो फार्मा ने नवंबर 2019 के पहले और दूसरे सप्ताह से इन दवाओं की वापसी शुरू की थी।

रैनिटिडीन और लिडोकाइन पर इस कार्रवाई को दवा में बाहरी तत्व की मौदूगी के लिए क्लास 2 वापसी के तौर पर परिभाषित किया गया है। इसे अनुपालन का उल्लंघन माना गया है और इससे रोगी के स्वास्थ्य पर तात्कालिक अथवा चिकित्सकीय तौर पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। जबकि एमियोडैरोन दवा में दृश्य अशुद्धियों की मौजूदगी के कारण क्लास 3 वापसी शुरू की गई है।

अप्रैल में यूएस एफडीए ने कंपनियों को अमेरिकी बाजार से रैनिटिडीन दवा को वापस मंगाने के लिए कहा था। पिछले महीने डॉ रेड्डीज और जीएसके सहित कई कंपनियों ने अमेरिकी बाजार से रेनिटिडीन जेनेरिक दवा को वापस मंगाया था।

इंडिया इंटरनैशनल एक्सचेंज पर ओएनजीसी का इश्यू

अमृता पिल्लई
मुंबई, 6 दिसंबर

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ओएनजीसी ने इंडिया इंटरनैशनल एक्सचेंज आईएफएससी (इंडिया आईएनएक्स) के वैश्विक प्रतिभूति बाजार पर अपने 30 करोड़ डॉलर के इश्यू को सूचबद्ध कराया है। यह इश्यू ओएनजीसी के यूरो मीडियम टर्म नोट (ईएमटीएन) कार्यक्रम के तहत जारी किया गया है।

इंडिया आईएनएक्स ने एक बयान में कहा है कि यह इश्यू 3.375 फीसदी कूपन दर के साथ आएगा और वह 2029 में परिपक्व होगा। एक्सचेंज ने कहा है कि ओएनजीसी ने इस एक्सचेंज के वैश्विक प्रतिभूति बाजार पर अपने 2 अरब डॉलर के मीडियम टर्म नोट (एमटीएन) कार्यक्रम स्थापित किया है और 20 करोड़ डॉलर का यह इश्यू उसी कार्यक्रम का हिस्सा है।

ईएमटीएन कार्यक्रम के लिए कोई प्रतिबद्धता नहीं की गई है और इसके तहत कुछ भी करने के लिए वित्त पोषण की जरूरत होगी। ओएनजीसी उन चुनिंदा कंपनियों में शामिल है जिन्होंने ईएमटीएन कार्यक्रम स्थापित किया है। साथ ही वह ऐसा करने वाली भारत की पहली सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं गैस कंपनी है।

ओएनजीसी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक शशि शेखर ने कहा, 'इंडिया आईएनएक्स के वैश्विक प्रतिभूति बाजार पर अपने 2 अरब डॉलर के ईएमटीएन कार्यक्रम के तहत 30 करोड़ डॉलर के इश्यू को गिफ्ट सिटी में आईएफएससी के इंडिया आईएनएक्स पर सूचीबद्ध कराते हुए हमें खुशी हो रही है। यह अन्य अंतरराष्ट्रीय बाजारों की तरह रकम जुटाने के लिए अंतरराष्ट्रीय निवेशकों तक पहुंचने का अवसर प्रदान करेगा। यह अनुपालन रिपोर्टिंग के लिए एकल खिड़की की सुविधा भी उपलब्ध कराएगा।'

इंडिया आईएनएक्स के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्याधिकारी वी बालसुब्रमण्यन ने कहा, '2 अरब डॉलर का ईएमटीएन कार्यक्रम इंडिया आईएनएक्स की नियामकीय मजबूती और पारदर्शिता को दर्शाता है। इससे भारत सरकार के उस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।'

एचयूएल से प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हो रही नेस्ले

विवेट सुजन पिंटो और अर्णव दत्ता
मुंबई/नई दिल्ली, 6 दिसंबर

उपभोक्ता क्षेत्र की कंपनी नेस्ले इंडिया हेल्थ फूड ड्रिंक के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हो रही है क्योंकि एचयूएल संग जीएसके कंज्यूमर हेल्थकेयर का विलय करीब है। उद्योग के सूत्रों ने कहा, अगस्त में वैश्विक ब्रांड माइलो की दोबारा पेशकश के साथ नेस्ले को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है और कंपनी इसके कुछ और वेरियंट पेश कर सकती है क्योंकि हॉर्लिक्स व बूस्ट जैसे ब्रांड के जरिए आगे बढ़ने वाली है, जिसका अधिग्रहण वह विलय के बाद करेगी।

पिछले महीने एचयूएल ने स्टॉक एक्सचेंज को भेजी सूचना में संकेत दिया था कि जीएसके कंज्यूमर का विलय करने के लिए उसे एनसीएलटी के मुंबई पीठ की मंजूरी मिल गई है। हालांकि इस विलय के लिए उसे चंडीगढ़ पीठ की मंजूरी की प्रतीक्षा है, जिसके बारे में उद्योग के सूत्रों ने कहा कि यह जनवरी के आखिर तक पूरा हो सकता है।

कंपनी के अधिकारियों ने कहा, अगस्त में दोबारा पेशकश के बाद माइलो को एनर्जी ड्रिंक के तौर पर स्थापित किया गया है और यह तीन प्रॉडक्ट फॉर्मेट टिन, टेट्रापैक और रेग्युलर पैक में उपलब्ध है।

टिन व रेग्युलर पैक घरों में उपभोग के लक्ष्य के साथ उतारा गया है क्योंकि यह पाउडर के रूप में है। टेट्रापैक और रेडि टु ड्रिंक सफर कर रहे उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर उतारा गया है।

माइलो टेट्रापैक, टिन व रेग्युलर पैक के मुकाबले देश भर में उपलब्ध है। टिन व रेग्युलर पैक को देश के पश्चिम व दक्षिण भारत के बाजारों में उतारा गया है। सूत्रों ने कहा कि यह रणनीति माइलको के लिए उन जगहों पर आधार बनाने के लिए है, जहां हेल्थ फूड ड्रिंक का उपभोग काफी ज्यादा होता है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु अहम बाजार है जहां माइलो का वितरण आक्रामक तौर पर किया जा रहा है। इस बाजार में हॉर्लिक्स भी मजबूत है।

वैश्विक स्तर पर नेस्ले मलेशिया, सिंगापुर, थाइलैंड और फिलिपींस को माइलो के लिए अहम बाजार मानती है और इस ब्रांड का भारत में भी प्रसार करना चाह रही है, जहां इसे पहली बार 2017 में उतारा गया। माइलो टेट्रापैक भारत में 2017 में उतारा गया और इस साल अगस्त में इसे दोबारा पेश किया गया।

उद्योग के सूत्रों का कहना है कि दूसरी ओर एचयूएल हेल्थ फूड ड्रिंक में अग्रणी स्थिति बनाए रखने के लिए हर तरह का प्रॉडक्ट फॉर्मेट उतारने पर विचार कर रही है। उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा, हॉर्लिक्स व बूस्ट की वॉल्यूम हिस्सेदारी 7,000 करोड़ रुपये के बाजार में संयुक्त रूप से करीब 65 फीसदी है। वॉल्यूम के लिहाज से हेल्थ फूड ड्रिंक 12 फीसदी सालाना की रफ्तार से बढ़ रहा है, वहीं वैल्यू के लिहाज से यह श्रेणी 9 फीसदी सालाना की रफ्तार से बढ़ रही है।

हॉर्लिक्स, बूस्ट और माइलो के अलावा जाइडस वेलनेस की तरफ से अधिग्रहीत कॉम्पलान, मोंडलीज इंडिया की बॉर्नवीटा और ऐबट व दनोन की क्रमश: पीडियाश्योर व प्रोटीनेक्स बाजार में कुछ अन्य अहम ब्रांड हैं।

पिछले साल हॉर्लिक्स व बूस्ट के अधिग्रहण में एचयूएल ने नेस्ले को पीछे छोड़ दिया था और कंपनी ने जीएसके कंज्यूमर का खुद में विलय करने के लिए करीब 32,000 करोड़ रुपये देने की पेशकश की थी।

यूनिलीवर का सबसे बड़ा बाजार होगा भारत: एडलवाइस

विवेट सुजन पिंटो
मुंबई, 6 दिसंबर

वित्त वर्ष 2027 के आखिर तक उपभोक्ता क्षेत्र की दिग्गज यूनिलीवर के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर सबसे बड़ी सहायक कंपनी बन सकती है और यह अमेरिकी इकाई से भी आगे निकल सकती है, जो अभी यूनिलीवर के लिए सबसे बड़ी इकाई है। यह अनुमान ब्रोकरेज फर्म एडलवाइस ने बुधवार को जारी एक रिपोर्ट में लगाया है, जो सालाना आधार पर 9 फीसदी की अनुमानित बढ़त पर आधारित है। यह बढ़त यूनिलीवर के बाजारों में सबसे तेज होगी।

यूनिलीवर के लिए एचयूएल पहले ही वॉल्यूम के लिहाज से सबसे बड़ी कंपनी है, जैसा कि चेयरमैन और प्रबंध निदेशक संजीव मेहता ने हालिया कन्फ्रेंस में कहा था। भारत में 98 फीसदी परिवार एक या एक से ज्यादा एचयूएल ब्रांड का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा था, देश भर में मौजूद कंपनी की फैक्टरी में 45 अरब इकाइयां उत्पादित होती हैं और भविष्य के लिए कंपनी डिजिटल कार्यक्रम तैयार कर रही है।

वैल्यू के लिहाज से भारतीय इकाई अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है, जो अभी यूनिलीवर के वैश्विक कारोबार 4 लाख करोड़ रुपये में करीब 10 फीसदी का योगदान करता है। यूनिलीवर के राजस्व में अभी अमेरिका का योगदान 16.3 फीसदी है।

राजस्व 77,000 करोड़ रुपये पर पहुंच जाएगा, अमेरिका से ज्यादा होगा

एडलवाइस ने कहा, वित्त वर्ष 2027 में एचयूएल का राजस्व वित्त वर्ष 2019 के 38.579 करोड़ रुपये के मुकाबले 77,000 करोड़ रुपये पर पहुंच जाएगा। दूसरी ओर अमेरिकी इकाई का राजस्व वित्त वर्ष 2027 तक 76,000 करोड़ रुपये पर पहुंचेगा, जो राजस्व की सालाना 2 फीसदी की अनुमानित रफ्तार पर आधारित है। वित्त वर्ष 2019 में अमेरिकी इकाई का कारोबार 65,693 करोड़ रुपये रहा था।

एडलवाइस ने यह भी कहा कि एचयूएल वित्त वर्ष 2025 में अमेरिकी इकाई के राजस्व के पार निकल जाएगी, अगर तब तक यह और कंपनी का अधिग्रहण कर लेती है। मेहता के नेतृत्व में एचयूएल ने इंदुलेखा, आदित्य मिल्क और जीएसके कंज्यूमर का अधिग्रहण किया है। इन कंपनियों का एचयूएल में विलय की प्रक्रिया चल रही है। कंपनी डेयरी जैसे क्षेत्रों में और अधिग्रहण कर सकती है क्योंकि वह अपने पोर्टफोलियो की खाई पाटना चाहती है।

पहुंच के लिहाज से एचयूएल पहले ही देश की सबसे बड़ी कंपनी है और उसके उत्पाद करीब 90 लाख आउटलेट तक पहुंचते हैं जबकि डाबर के 63 लाख आउटलेट और आईटीसी के उत्पाद 60 लाख स्टोर तक पहुंचते हैं।

बीएस बातचीत

'ई-वाहन श्रेणी में अग्रणी होने की योजना'

चीनी स्वामित्व वाली ब्रिटेन की कार कंपनी मॉरिस गैरेजेज ने हुंडई कोना के बाद भारत की दूसरी पूर्ण इलेक्ट्रिक एसयूवी जेडएस मॉडल का अनावरण किया है। एमजी मोटर्स इंडिया के प्रमुख **राजीव चाबा** की **अरिंदम मजूमदार** से बातचीत में के मुख्य अंश:

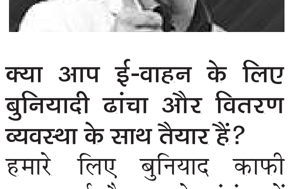

भारत में एमजी मोटर्स के दो उत्पाद हैं और दूसरा उत्पाद अधिक कीमत वाली प्रीमियम श्रेणी में है। क्या इससे जोखिम अधिक नहीं दिख रहा है?
भारत के लिए पहले दिन से ही कंपनी का दृष्टिकोण अलग रहा है। यहां हम कैसे मुकाबला कर सकते हैं जहां शीर्ष दो कंपनियों की लगभग 70 फीसदी बाजार हिस्सेदारी है। इसलिए हमें अलग उत्पादों की जरूरत है। एमजी हेक्टर को लॉन्च करते समय हमने कई सवालों का सामना किया था जैसे क्या भारत कनेक्टेड कार के लिए तैयार है आदि। लेकिन उस कार के आकार और सुविधाओं के कारण हमें काफी सफलता मिली। हम प्रौद्योगिकी के मोर्चे पर अग्रणी होना चाहते हैं।

क्या आप ई-वाहन के लिए बुनियादी ढांचा और वितरण व्यवस्था के साथ तैयार हैं?
हमारे लिए बुनियाद काफी महत्त्वपूर्ण है। हमारे संयंत्र में क्षमता की कमी नहीं है लेकिन हमने यह कहते हुए खुद को सीमित किया है कि हम एक निर्धारित सीमा से अधिक मासिक उत्पादन नहीं करेंगे। बीएस6 के बाद हम उत्पादन बढ़ाएंगे। हमने काफी सोच समझकर यह निर्णय लिया है क्योंकि हम अपनी व्यवस्था को स्थिर करना चाहते हैं।

क्या आप 10 लाख रुपये कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहन की दौड़ में शामिल हैं?
हम उसमें अग्रणी होना चाहते हैं।

क्या इस श्रेणी में आपकी प्रतिस्पर्धा हुंडई से होगी?
आंकड़ों पर गौर करते हुए मुझे नहीं लगता है कि इस श्रेणी में कोई प्रतिस्पर्धा है। फिलहाल यह दोनों के लिए फायदेमंद रहेगी।

सरकार ले सकती है 80 हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त उधार

अनूप रॉय
मुंबई, 6 दिसंबर

भारतीय रिजर्व बैंक के अस्थायी विराम ने बाजार को संकेत दे दिया है कि केंद्रीय बैंक को राजकोषीय घाटे का आंकड़ा लक्ष्य के पार निकल जाने का संदेह है और सरकार अतिरिक्त उधार ले सकती है। आरबीआई बजट के आंकड़ों की प्रतीक्षा कर रहा है।

मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए राजकोषीय घाटा 3.3 फीसदी के लक्ष्य के मुकाबले 3.6–3.7 फीसदी पर जा सकता है। बाजार का मानना है कि इस घाटे को पाटने के लिए अतिरिक्त उधारी 50 से 80 हजार करोड़ रुपये हो सकती है। नीलामी के कैलेंडर में वित्त वर्ष के आखिरी महीने को खाली रखा गया है। बॉन्ड डीलरों ने कहा, अल्पावधि वाले मुद्रा बाजार की दरों ने 15 आधार अंकों की कटौती को पूरी तरह प्रतिबिंबित किया है, वहीं राजकोषीय चिंता के चलते 10 वर्षीय बॉन्ड प्रतिफल ने 89 आधार अंक प्रेषित किया है।

10 वर्षीय बॉन्ड प्रतिफल एक बार फिर पांच आधार अंक बढ़ा जबकि गुरुवार को यह 15 आधार अंक उछला था। इस तरह से शुक्रवार को यह 6.665 फीसदी पर बंद हुआ।

बॉन्ड बाजार

- बजट के आंकड़ों की आरबीआई की प्रतीक्षा ने बॉन्ड बाजार को चौंकाया
- 10 वर्षीय प्रतिफल दिसंबर के आखिर तक बढ़कर 6.75 फीसदी हो सकता है
- राजकोषीय घाटा 3.6-3.7 फीसदी पर पहुंच सकता है
- राजस्व में कमी, निजीकरण में देर है मुख्य चिंता
- इस वित्त वर्ष में एयर इंडिया की बिक्री पूरी होने पर बाजार को है संदेह
- छोटी बचत के आंकड़े काफी मजबूत हैं
- अतिरिक्त उधारी 50 से 80 हजार करोड़ रुपये हो सकती है
- पर्याप्त नकदी से उधारी के समायोजन में मिल सकती है मदद

वरिष्ठ बॉन्ड डीलर ने कहा, 10 वर्षीय प्रतिफल 25 आधार अंकों की कटौती समाहित की है। अगर कटौती होती है यह बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं जताता। इसके अलावा आगामी दो–तीन महीने में महंगाई 5 फीसदी से ऊपर बने रहने के अनुमान को देखते हुए यह करीब–करीब निश्चित था कि आरबीआई के पास कटौती की कोई गुंजाइश नहीं होगी।

बॉन्ड डीलर ने कहा, भविष्य में कटौती की संभावना भी शून्य है। प्रतिफल भी उसे समायोजित करेगा। दिसंबर के आखिर तक 10 वर्षीय प्रतिफल बढ़कर 6.75 फीसदी पर पहुंच सकता है।

राजकोषीय घाटे को पाटना, नियोजित व संभावित तौर पर अतिरिक्त विनिवेश और छोटी बचत योजनाओं के जरिए संग्रह पर निर्भर है। लेकिन इस वित्त वर्ष में महज चार महीने बचे हैं, लिहाजा बाजार को मुश्किल लग रहा है कि सरकार एयर इंडिया को बेच पाएगी और यहां तक कि बीपीसीएल व अन्य नियोजित निजीकरण हासिल किया जा सकेगा। अगर जल्दबाजी में किया गया तो इस पर भी चिंता होगी कि क्या इसका मूल्यांकन उचित होगा।

एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के प्रमुख (फिक्स्ड इनकम) बद्रीश कुलहल्ली ने कहा, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर संग्रह अनुमान के मुकाबले काफी कम है, जिससे अतिरिक्त उधारी की आशंका है।

उन्होंने कहा, कुछ भरपाई छोटी बचत योजनाओं के संग्रह से हो सकती है। बाकी का वित्त पोषण अतिरिक्त विनिवेश से हो सकता है जबकि बाकी अतिरिक्त उधारी से पूरी हो सकती है।

प्रत्यक्ष कर संग्रह और जीएसटी संग्रह में गिरावट के कारण बॉन्ड बाजार आश्वस्त है कि सरकार अतिरिक्त लाभांश के लिए सार्वजनिक कंपनियों पर निर्भर होगी और वह छोटी बचत योजनाओं पर भी निर्भर रहेगी। यही वजह है कि सरकार छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज घटाना नहीं चाहती जबकि आरबीआई ने दिसंबर की नीति में स्पष्ट कहा है कि छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें समायोजित करने की दरकार है। हालांकि बाजार में हर कोई सरकार की तरफ से भारी–भरकम अतिरिक्त उधारी की संभावना नहीं जता रहे। अगर ऐसा होता है तब भी बाजार में इसे समाहित करने की क्षमता है।

हरिहर कृष्णमूर्ति ने कहा, अतरिक्त नकदी इतनी है कि अतिरिक्त उधारी आसानी से समाहित हो जाएगी।

बीएस बातचीत

एक्सप्रेस बिजनेस पर देंगे ध्यान

ई-कॉमर्स कारोबार के कारण एक्सप्रेस इंडस्ट्री में बढ़त की मजबूत संभावना है और एक्सप्रेस उद्योग की अग्रणी कंपनी गति के अधिग्रहण के जरिये अलकार्गो इस मौके को भुनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। **अदिति दिवेकर** को दिए साक्षात्कार में अलकार्गो के चेयरमैन **शशि किरण शेट्टी** ने कंपनी को आगे बढ़ाने की योजना पर विस्तार से बातचीत की। पेश हैं मुख्य अंश...

गति की हिस्सेदारी खरीद से आपको भारी निवेश वाले कोल्ड चेन बिजनेस में मौजूदगी का अवसर दिया है। इस कारोबार को आगे बढ़ाने की क्या योजना है?

कोल्ड चेन में हमारा इरादा कम से कम शुरू में बड़ी पूंजी नहीं लगाने का है क्योंकि हमें इस कारोबार को समझना होगा। हम कोल्ड चेन में गठजोड़ करने या फ्रैंचाइजी मॉडल बनाने पर विचार कर सकते हैं। हमें इस मोर्चे पर अभी काम करना होगा। हम गति के लास्ट माइल व एक्सप्रेस क्षेत्र में ध्यान केंद्रित करेंगे।

एक्सप्सेस और लास्ट-माइल डिलिवरी कारोबार को बढ़ाने के लिए आपकी क्या योजना है?

एक्सप्रेस व लास्ट माइल कारोबार में हम कार्यक्षमता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करेंगे क्योंकि एक्सप्रेस कारोबार में बढ़त की काफी संभावना है। देश के 747 जिलों में से 727 में गति की मौजूदगी है। लक्ष्य है वॉल्यूम बढ़ाने और इस कारोबार में मार्जिन दोगुना कर 10 फीसदी पर ले जाना का। हम ई–कॉमर्स के साथ कारोबार बढ़ाएंगे, जो हमें एक्सप्रेस कारोबार में और मौके देगा। ई–कॉमर्स में हम आउटसोर्सिंग करने पर विचार करेंगे, न कि इसके प्रबंधन में शामिल होंगे।

गति की हिस्सेदारी खरीद के बाद अलकार्गो समेत आपका कुल कर्ज कितना होगा? कर्ज में कमी लाने के लिए आपकी क्या योजना है?

मौजूदा विस्तार और गति की हिस्सेदारी से हमारा कर्ज 1,200 करोड़ रुपये होगा। हमारी योजना हिस्सेदारी बेचने और पांच लॉजिस्टिक्स पार्क के क्षेत्र में अल्पांश हिस्सेदार बनने की है, जो हमारा कर्ज करीब 90 फीसदी कम कर देगा। हम अगले दो–तीन हफ्ते में लॉजिस्टिक्स पार्क की हिस्सेदारी बिक्री की घोषणा करेंगे।

वी जी सिद्धार्थ के स्वामित्व वाली सिकल लॉजिस्टिक्स के अधिग्रहण की क्या स्थिति है?

अभी सिकल लॉजिस्टिक्स की जांच–परख हो रही है, ऐसे में हम समयसीमा नहीं दे सकते। सिकल की मौजूदगी सीएफएस/आईसीडी कारोबार में है, लेकिन उसकी मौजूदगी वहां भी है जहां अलकार्गो नहीं है। इसी वजह से इस अधिग्रहण में हमारी रुचि है।

आरबीएल बैंक ने जुटाए 2,025 करोड़ रुपये

निधि राय
मुंबई, 6 दिसंबर

निजी क्षेत्र के आरबीएल बैंक ने पात्र संस्थागत नियोजन (क्यूआईपी) से संस्थागत निवेशकों से 2,025.27 करोड़ रुपये जुटाए हैं, जिसका इस्तेमाल कारोबार को आगे बढ़ाने में किया जाएगा। यह क्यूआईपी 2 दिसंबर को खुला और 5 दिसंबर को बंद हुआ। आरबीएल बैंक ने एक बयान में कहा कि 351 रुपये प्रति शेयर पर 2,025 करोड़ रुपये का क्यूआईपी पूरा हो गया और इसके तहत 5.77 करोड़ इक्विटी का आवंटन हुआ। बैंक के बयान में कहा गया है, इस इश्यू को देसी व विदेशी क्यूआईबी की तरफ से मजबूत मांग देखने को मिली। म्युचुअल फंडों और बीमा कंपनियों समेत देसी निवेशकों को कुल क्यूआईपी का 60 फीसदी आवंटित किया गया जबकि बाकी एशिया व यूरोप के विदेशी संस्थागत निवेशकों को।

बैंक ने कहा, हमने अपने क्रेडिट कार्ड पार्टनर बजाज फाइनैंस की भागीदारी देखी और अन्य नए निवेशक खास तौर से विदेशी संस्थागत निवेशकों की भागीदारी देखने को मिली, लिहाजा बैंक के शेयरधारकों का आधार विशाखित हुआ। आरबीएल बैंक के एमडी व सीईओ विश्ववीर आहूजा ने कहा, इस पूंजी से पूंजी पर्याप्तता में इजाफा हुआ है और बढ़त के मौके को पूंजीकृत करने के लिए हमें बेहतर स्थिति में ला दिया है।

फ्रैंकलिन टेम्पलटन ने एस्सेल इन्फ्राप्रोजेक्ट्स में निवेश बट्टे खाते में डाला

जश कृपलानी
मुंबई, 6 दिसंबर

एस्सेल समूह की इन्फ्रास्ट्रक्चर इकाई एस्सेल इन्फ्राप्रोजेक्ट्स में फ्रैंकलिन टेम्पलटन की चार योजनाओं के निवेश की एनएवी में गुरुवार को 0.4 प्रतिशत और 2 प्रतिशत के बीच गिरावट देखी गई। कंपनी के डिबेंचर में निवेश को बट्टे खाते में डाले जाने के बाद इन योजनाओं की एनएवी में कमजोरी देखने को मिली है।

वैल्यू रिसर्च से प्राप्त आंकड़े के अनुसार, फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड (योजना की परिसंपत्तियों का 4.1 प्रतिशत निवेश) ने गुरुवार को अपनी एनएवी में दो प्रतिशत की गिरावट दर्ज की। शॉर्ट टर्म इनकम प्लान और क्रेडिट रिस्क फंड (प्रत्येक का 1.25 प्रतिशत निवेश) में 0.76 प्रतिशत और 0.77 प्रतिशत की कमी आई। डायनेमिक एक्रुअल फंड में 0.4 प्रतिशत की गिरावट आई।

गुरुवार को ब्रिकवर्क रेटिंग्स ने कंपनी की दीर्घावधि और अल्पावधि बैंक देनदारियों की रेटिंग घटाकर ग्रेड 'डी' कर दी। बैंक ऋणों के निपटान में विलंब का हवाला देते हुए इस रेटिंग में कमी की गई है। रेटिंग एजेंसी का यह भी कहना है कि कंपनी उसके साथ पूरी तरह सहयोग नहीं कर रही थी।

एक सूत्र के अनुसार, फ्रैंकलिन टेम्पलटन एमएफ की प्रतिभूतियों के लिए रेटिंग में इस तरह की गिरावट नहीं की गई है, लेकिन फंड हाउस ने सक्रिय कदम के तौर पर निवेश को बट्टे खाते में डालने का निर्णय लिया।

अपने समूह से सीधे संपत्ति नहीं खरीद पाएंगी एआरसी

संपत्ति पुनर्गठन कंपनियों (एआरसी) को अपने समूह या मूल बैंक से द्विपक्षीय आधार पर परिसंपत्ति खरीदने पर आरबीआई ने शुक्रवार को रोक लगा दी। अपनी वेबसाइट पर केंद्रीय बैंक ने कहा कि एआरसी उस बैंक या वित्तीय संस्थान से वित्तीय परिसंपत्तियां नहीं खरीद सकती, जो एआरसी की प्रवर्तक है। या फिर उस बैंक या वित्तीय संस्थान से भी एआरसी संपत्ति नहीं खरीद पाएगी जो या तो एआरसी की लेनदार हो या फिर एआरसी की तरफ से अपने परिचालन के लिए जुटाई गई रकम में उसने भागीदारी की हो।

दस फीसदी फिसला येस बैंक का शेयर

निधि राय
मुंबई, 6 दिसंबर

येस बैंक का शेयर करीब 10 फीसदी टूट गया जब वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने गुरुवार को येस बैंक की लंबी अवधि की विदेशी मुद्रा रेटिंग बीए–3 से घटाकर बी–2 कर दिया। यह शेयर बीएसई पर 9.82 फीसदी की गिरावट के बाद 56 रुपये पर बंद हुआ।

मूडीज ने कहा है कि बैंक के पास दबाव वाली परिसंपत्तियां हैं, जो उसकी फंडिंग व नकदी पर दबाव बढ़ा सकता है। यह बैंक के एकल क्रेडिट प्रोफाइल पर अतिरिक्त जोखिम भी सृजित कर सकता है।

रेटिंग एजेंसी का मानना है कि सितंबर 2019 के आखिर में येस बैंक का कॉमन इक्विटी टियर–1 अनुपात 8.7 फीसदी रहा, जो तब और दबाव में आ सकात है अगर बैंक अगली कुछ तिमाहियों में नई पूंजी जुटाने में नाकाम रहता है। मूडीज ने कहा कि निजी क्षेत्र के लेनदार की फंडिंग व नकदी देश के अन्य निजी बैंकों के मुकाबले कमजोर है।

कारों का वितरण विकेंद्रित करेगी टाटा मोटर्स

शैली सेठ मोहिले
मुंबई, 6 दिसंबर

टाटा मोटर्स कम से कम सात क्षेत्रीय स्टॉकयार्ड स्थापित करने की प्रक्रिया में है क्योंकि कंपनी वितरण की सक्षम व्यवस्था चाह रही है। इससे डीलरों के पास वाहनों का पहुंचना सुनिश्चित होगा और खरीदारों को अधिकतम तीन दिन में डिलिवरी मिल सकेगी।

टाटा मोटर्स के अध्यक्ष (यात्री वाहन कारोबार) मयंक पारिख ने कहा, यह कदम डीलरों पर वित्तीय बोझ घटाने के इरादे से भी उठाया जा रहा है क्योंकि यह इन्वेंट्री की लागत का भी ध्यान रखेगा।

पारिख ने कहा, कंपनी का गुवाहाटी स्टॉकयार्ड पहले से ही परिचालन में है और मौजूदा वित्त वर्ष के आखिर तक तीन और स्टॉकयार्ड स्थापित हो जाएंगे जबकि बाकी अगले साल के मध्य तक स्थापित हो जाएगा।

प्रदूषण पर काम करने के लिए सांसदों का समूह

बीएस संवाददाता
नई दिल्ली, 6 दिसंबर

विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों ने भारत में वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने को लेकर प्रतिबद्धता जताई है।

पर्यावरण, वन पर संसदीय समिति के चेयरमैन और कांग्रेस सरकार में पर्यावरण मंत्री रहे जयराम रमेश, भाजपा सांसद जगदंबिका पाल, तेलुगूदेशम पार्टी के राम मोहन नायडू, तृणमूल कांग्रेस की काकोली घोष, द्रमुक के टी सुभति, भाजपा के केजे अल्फोंस के अलावा अन्य कई सांसदों ने स्वच्छ हवा के लिए एक सर्वदलीय सांसदों का समूह बनाने पर सहमति जताई है।

पाल शहरी विकास पर बनी संसद की समिति के चेयरमैन हैं।

दिल्ली के शहरी बुनियादी ढांचे से जुड़े मामले, मेट्रो परिवहन और दिल्ली विकास प्राधिकरण का कामकाज केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय देखता है।

सांसदों ने गुरुवार शाम मुलाकात की और भारत में बढ़ते प्रदूषण से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा की।

लघु वित्त बैंक बनने की राह बनी

निधि राय
मुंबई, 6 दिसंबर

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपने वित्तीय समावेशन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए ऑन टैप बैंक लाइसेंसिंग पर अंतिम दिशानिर्देश जारी कर दिए। इससे पहले रिजर्व बैंक ने साझेदारों के साथ इस के बारे में चर्चा की थी। बैंकरों और विश्लेषकों की राय है कि इन नियमों से लघु वित्त कंपनियों और सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को एसएफबी में प्रवेश करने का आधार मिल सकता है।

फिनकेयर स्मॉल फाइनैंस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजीव यादव ने कहा, 'इस कदम से देश में वित्तीय सेवाओं के दायरे के विस्तार में तेजी आएगी। इसके बाद अब प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) को स्वेच्छा से लघु वित्त बैंकों (एफएफबी) में तब्दील होना संभव होगा। इन बैंकों में जमाकर्ताओं को ज्यादा स्थायित्व और सुरक्षा मिल सकेगी।'

विशेषज्ञ मानते हैं कि स्वतंत्र माइक्रोफिन, फ्यूजन माइक्रोफाइनेंस, स्पंदन स्फूर्ति फाइनेंशियल, अन्नपूर्णा फाइनेंस और सैटिन क्रेडिटकेयर जैसे नाम इस योजना का लाभ लेने में सबसे पहले आगे आ सकते हैं।

एनबीएफसी के एक बैंकर ने बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा, 'हां हम इस विकल्प को अपनाने पर विचार करेंगे क्योंकि इससे हमारी पहुंच जमाओं तक होगी जो फिलहाल नहीं है। लेकिन हमारे लिए फिलहाल यह कह पाना जल्दबाजी होगी कि हम इसे अपनाने जा रहे हैं। फिलहाल हम दूसरी चीजों पर काम कर रहे हैं और इस दिशा में कोई कदम उठाने से पहले इसका समुचित विश्लेषण करेंगे।'

केंद्रीय बैंक ने इससे पहले एसएफबी के लाइसेंसिंग के लिए नवंबर 2014 में दिशानिर्देश जारी किए थे जिसके बाद 10 आवेदकों को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी। इनमें से आठ एमएफआई थे और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एकमात्र गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी थी और कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक पंजाब में स्थानीय क्षेत्रीय बैंक था।

एपीएमईए, बैंकिंग सॉल्यूशंस, एफआईएस के प्रबंध निदेशक महेश राममूर्ति ने कहा, 'पेमेंट बैंकों के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस लेने से पूर्व 5 वर्ष परिचालन पूरा करने की शर्त थोड़ी लंबी प्रतीत होती है। जबकि पेमेंट बैंक अपने कारोबारी मॉडल को और अधिक मजबूत करने के लिए अपने उत्पाद या सेवाओं को विस्तारित करने पर विचार कर रहे हैं। रिजर्व बैंक की ओर से इस बात को दोहराया जाना कि स्मॉल फाइनेंस बैंकों के पास यूनिवर्सल बैंकिंग का लाइसेंस लेने का रास्ता होगा भरोसा बंधाता है और यह एसएफबी के लिए सकारात्मक खबर है।'

यह कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि एनबीएफसी और एमएफआई इस मौके को लपक लेंगे। लेकिन वे इसको लेकर विचार करेंगे क्योंकि एसएफबी के लाइसेंस लेने के पक्ष में सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जमा स्वीकार करने की अनुमति दी गई है। एक विशेषज्ञ ने कहा, 'मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इसको तुरंत अपना लेगा लेकिन हां वे इसको लेकर विचार जरूर करेंगे। यह उन्हें सहूलियत देगा।'

अब एनबीएफसी इधर उधर देखने की बजाय अपने कारोबार पर ही ध्यान लगाना चाहती हैं और आपको इस बात पर सहमत होना होगा कि एसएफबी बाजार पहले से ही बहुत प्रतिस्पर्धी है।

लाइसेंसिंग पर दिशानिर्देश जारी

- छोटे एनबीएफसी और एमएफआई बन पाएंगे लघु वित्त बैंक
- नए दिशानिर्देशों के बाद अब मौजूदा एनबीएफसी और एमएफआई के लिए एसएफबी एक दिलचस्प कारोबारी मॉडल बना
- केंद्रीय बैंक ने इससे पहले एसएफबी के लाइसेंसिंग के लिए नवंबर 2014 में दिशानिर्देश जारी किए थे जिसके बाद 10 आवेदकों को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी।

बीओए का गिफ्ट सिटी में खुला केंद्र

विनय उमरजी
अहमदाबाद, 6 दिसंबर

बैंक आफ अमेरिका कॉर्प (बीओए) ने शुक्रवार को गुजरात इंटरनैशनल फाइनैंस टेक सिटी (गिफ्ट सिटी) में अपना ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर शुरू कर दिया। यह पहला विदेशी बैंक है, जिसने इंटरनैशनल फाइनैंशियल सर्विस सेंटर (आईएफएससी) में परिचालन शुरू किया है। नए केंद्र में बीओए को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा में डेट फाइनैंस जुटाने की अनुमति होगी। विदेशी बैंक ने गिफ्ट-आईएफएससी पर दो इंडियन बॉन्ड ऑक्शन शुरू किया है।

बैंक आफ अमेरिका इंडिया की प्रेसीडेंट और कंट्री हेड काकू नखाटे ने कहा, 'हम भारती कॉर्पोरेट्स को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वे इसे बॉन्डों की नीलामी के लिए प्लेटफॉर्म के रूप में विचार करें। हमने जिन दो बॉन्डों को सूचीबद्ध किया है, वे इंडसइंड बैंक और येस बैंक के लिए हैं। लग्जमबर्ग और सिंगापुर के अलावा वे गिफ्ट-आईएफएसी में सूचीबद्ध हैं।'

आगे नखाटे ने कहा कि बैंक फाइनैंशियल टेक्नोलॉजी (फिनटेक) सेक्टर के आसपास एक माहौल बनाने पर विचार कर रहा है। उन्होंने कहा, 'हम यहां एआई, रोबोटिक्स और फिनटेक में संभावाएं तलाश रहे हैं, जिससे हम दुनिया तक पहुंच सकें और गिफ्ट सिटी ने इस तरह की नवोन्मेषी सोच को लेकर हाथ आगे बढ़ाया है।' बैंक आफ अमेरिका के मुख्य परिचालन और टेक्नोलॉजी ऑफिसर कैथरिन पी बेसेंट ने कहा कि गिफ्ट सिटी के आईएफएससी में इस स्थल के लिए 500 लोगों को रखा गया है।

जीडीपी आंकड़े व उपभोक्ता सर्वे की तुलना से निष्कर्ष संभव नहीं : समिति

सोमेश झा
नई दिल्ली, 6 दिसंबर

- समिति ने विभिन्न खाद्य एवं अखाद्य वस्तुओं पर व्यय में कमी, खासकर ग्रामीण इलाकों में कमी को लेकर स्वीकार्य स्पष्टीकरण दिया है
- इसे सर्वे रिपोर्ट 2017-18 में जगह मिल सकती है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की उपभोक्ता व्यय रिपोर्ट 2017-18 की समीक्षा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित समिति ने कहा है कि सर्वे के परिणामों की तुलना सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) से निकले खपत के आंकड़ों से नहीं की जा सकती है। समिति ने विभिन्न खाद्य एवं अखाद्य वस्तुओं पर व्यय में कमी, खासकर ग्रामीण इलाकों में कमी को लेकर स्वीकार्य स्पष्टीकरण दिया है। इसे सर्वे रिपोर्ट 2017-18 में जगह मिल सकती है। उम्मीद की जा रही है कि दो महीने के भीतर रिपोर्ट जारी की जाएगी।

पिछले महीने बिजनेस स्टैंडर्ड ने खबर दी थी कि एनएसओ के 'परिवार में व्यय सर्वे के प्रमुख संकेतक' के मुताबिक 2011-12 से 2017-18 के बीच उपभोक्ता व्यय पिछले 4 दशक में पहली बार कम हुआ है, जिसमें इसमें अहम भूमिका घटी ग्रामीण मांग की रही।

बहरहाल खबर आने के बाद सरकार ने आंकड़ों की गुणवत्ता का हवाला देकरक सर्वे को स्वीकार न करने का फैसला किया था।

राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के चेयरमैन विमल कुमार रॉय ने बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा था कि कुछ प्रतिवाद के साथ रिपोर्ट 2 महीने में जारी की जाएगी क्योंकि परिवारों के व्यय में गिरावट की उचित वजहें हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि परिवार के व्यय में गिरावट इस बात का संकेत है कि गरीबी बढ़ी होगी।

इस समिति का गठन मुख्य सांख्यिकीविद प्रवीण श्रीवास्तव की अध्यक्षता में जुलाई में हुआ था, जिसे सर्वे आंकड़ों की वैधता की समीक्षा करनी थी।

समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि परिवार के खपत व्यय अनुपात और जीडीपी के निजी अंतिम खपत व्यय (पीएफसीई) में बहुत अंतर है क्योंकि इसमें वस्तुओं के अलग अलग समूह हैं। ऐसा 2011-12 और 2017-18 दोनों ही वर्षों में है और इन दोनों की तुलना करके किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है।

एनएसओ सर्वे रिपोर्ट में विभिन्न खाद्य व गैर खाद्य वस्तुओं पर परिवारों द्वारा मौद्रिक मूल्य के हिसाब से व्यय का ब्योरा होता है।

एनएससी सदस्य जीसी मन्ना की अध्यक्षता वाली समिति ने पाया था कि एनएसओ के खपत व्यय आंकड़ों और पीएफसीई के बीच अंतर 2011-12 और 2017-18 के बीच बढ़ा है। ऐसा सभी वस्तुओं के मामले में हुआ है। इसमें पाया गया कि 2011-12 को छोड़कर 1993-94 से दो अनुमानों के बीच अंतर धीरे धीरे बढ़ा है।

समिति ने कहा है, 'प्रशासनिक (जीडीपी) और सर्वे के आंकड़ों में तुलना करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचना संभव नहीं है क्योंकि उत्पादन आंकड़ों और परिवारों के कुल खपत व्यय के आंकड़ों में भारी अंतर है। उद्योगों, होटलों, रेस्टोरेंटों, मांस की दुकानों और इन जिंसों के निर्यात आदि में खपत का अध्ययन कठिन है।'

सरकार के आंकड़ों में किए गए दावे से समिति के निष्कर्षों का तालमेल नहीं है। सांख्यिकी मंत्रालय ने जब 2017-18 के सर्वे रिपोर्ट को अस्वीकार करने की घोषणा की थी तो प्रेस विज्ञप्ति में 15 नवंबर को कहा था कि 'न सिर्फ खपत पैटर्न में विचलन बढ़ा है बल्कि अन्य प्रशासनिक स्रोतों के आंकड़ों जैसे वस्तुओं और सेवाओं के वास्तविक उत्पादन से तुलना करें तो बदलाव नजर आता है।'

समिति ने इस बात को भी खारिज किया कि पहले के दौर के सर्वे की तुलना में तुलनात्मक रूप से प्रभावशाली लोगों के खपत के आंकड़ों की रिपोर्टिंग की गई है।

समिति ने सिफारिश की है कि आगे के सर्वे में सुधार के लिए कदम उठाए जाने चाहिए जिसमें समृद्ध तबके के लोगों को भी शामिल किया जाए और सर्वे का निष्कर्ष निकालते समय समवर्ती आधार पर आंकड़ों की जांच की जाए।

अयोध्या फैसले पर पुनर्विचार के लिए 5 याचिकाएं

अयोध्या में विवादित स्थल पर राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ करने संबंधी उच्चतम न्यायालय के 9 नवंबर के फैसले पर पुनर्विचार के लिए शुक्रवार को 5 याचिकाएं दायर की गईं।

इस फैसले पर पुनर्विचार के लिए अब मौलाना मुफ्ती हसबुल्ला, मोहम्मद उमर, मौलाना महफूजुर रहमान, हाजी महबूब और मिसबाहुद्दीन ने दायर की हैं। इन सभी पुनर्विचार याचिकाओं को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का समर्थन प्राप्त है।

तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाले सदस्यीय संविधान पीठ ने अपने सर्वसम्मति के फैसले में 2.77 एकड़ की विवादित भूमि की डिक्री राम लला विराजमान के पक्ष में की थी और अयोध्या में ही एक प्रमुख स्थान पर मस्जिद निर्माण के लिए उप्र सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ भूमि आवंटित करने का निर्देश केंद्र सरकार को दिया था।

याचिकाओं में से एक में कहा गया है कि यह याचिका दायर करने का मकसद इस महान राष्ट्र की शांति को भंग करना नहीं है लेकिन इसका मकसद है कि न्याय के लिए शांति सुखदायी होनी चाहिए। *भाषा*

दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है जीएसटी वसूली में घाटा

रामवीर सिंह गुर्जर
नई दिल्ली, 6 दिसंबर

- जीएसटी लागू होने के पहले साल 6 फीसदी, दूसरे साल 20 फीसदी था जीएसटी वसूली में घाटा
- चालू वित्त वर्ष में नवंबर तक यह घाटा बढ़कर 33 फीसदी

दिल्ली सरकार का जीएसटी प्रणाली में जीएसटी वसूली में घाटा लगातार बढ़ रहा है। जीएसटी लागू होने के पहले साल सरकार को जीएसटी वसूली में महज 6 फीसदी घाटा हुआ था, जो चालू वित्त वर्ष में नवंबर महीने तक बढ़कर करीब 33 फीसदी हो गया है। पिछले वित्त वर्ष में भी दिल्ली सरकार को लक्ष्य के अनुरूप जीएसटी वसूली न होने से 20 फीसदी से ज्यादा घाटा हुआ था। केंद्र सरकार के उलट दिल्ली सरकार को इस साल नवंबर महीने में पिछले साल नवंबर के मुकाबले करीब 14 फीसदी कम जीएसटी प्राप्त हुआ।

चालू वित्त वर्ष में दिल्ली सरकार के लिए जीएसटी वसूली का मासिक लक्ष्य 2,362 करोड़ रुपये है। इस हिसाब से नवंबर महीने तक सरकार को जीएसटी वसूली से 18,897 करोड़ रुपये मिलने चाहिए थे। लेकिन इस अवधि में 12,687 करोड़ रुपये ही मिले। इस तरह दिल्ली सरकार को चालू वित्त वर्ष नवंबर महीने तक तय लक्ष्य से जीएसटी वसूली में करीब 33 फीसदी घाटा हुआ है। हालांकि जीएसटी कानून के मुताबिक इस घाटे की क्षतिपूर्ति केंद्र सरकार से इस अवधि के लिए मिलने वाले 6,210 करोड़ रुपये जीएसटी मुआवजे से हो जाएगी। इस मुआवजा राशि में से दिल्ली सरकार को 2,568 करोड़ रुपये मिल चुके हैं और 3,642 करोड़ रुपये केंद्र सरकार के पास लंबित है।

दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन से मिलकर जीएसटी मुआवजे की इस लंबित राशि को जल्द जारी करने की मांग की है। दिल्ली जीएसटी विभाग के सूत्रों का कहना है कि भले ही जीएसटी वसूली में 33 फीसदी घाटे की पूर्ति मुआवजे से हो जाए, लेकिन लक्ष्य से इतना पिछड़ना चिंताजनक है। कम वसूली की वजह आर्थिक सुस्ती की मार है। राजस्व वसूली बढ़ने की सबसे ज्यादा आस त्योहारी सीजन से रहती है।

बीएस सूडोकू 3606

	3				1			6
1			6			2		
	9			5				
		1			6			8
8	4						9	1
9			8			3		
				6			4	
		2			7			5
3			4				6	

परिणाम संख्या 3605

1	9	7	5	3	8	4	6	2
3	4	2	1	7	6	8	5	9
6	8	5	9	4	2	7	3	1
5	2	9	3	8	4	6	1	7
7	3	8	2	6	1	9	4	5
4	1	6	7	9	5	3	2	8
8	7	1	4	5	3	2	9	6
2	6	4	8	1	9	5	7	3
9	5	3	6	2	7	1	8	4

कैसे खेलें?
हर रो, कॉलम और 3 बाई 3 के बॉक्स में एक से लेकर नौ तक की संख्या भरें।

आसान ★★☆☆☆

क्षेत्रीय मंडियों के भाव

उत्तर प्रदेश | राजस्थान | पंजाब

कानपुर
गेहूं लूज 2100/2110, जौ 1790/1800, चावल मसूरी 2275/2325, चावल मोटा 2150/2250, सरसों 4300/4325, तिल सफेद 9000/9100, सोया (टीन) 1450/1500, तेल सरसों कच्ची घानी वैट पेड (टीन)1560/1630,

लखनऊ
गेहूं दड़ा 2100/2125, गेहूं शरबती 2700/2800, चावल शरबती सेला 3800/3900, स्टीम 4300/4400, लालमती 3300/3400, चावल (सोना) 2900/2975,

चंदौसी
(प्रति किलो): मैन्था ऑयल 1440, बोल्ड क्रिस्टल (12 नं.)1548, फ्लैक 1465, डीएमओ 1023, टरपीन लैस बोल्ड 1540

मुजफ्फरनगर
गुड़ (40 किलो): लड्डू नया 950/1075, खुरपा 925/950,चाकू 810/815, रसकट 820/825, शक्कर 1150/1180, चीनी मिल डिली. (क्विं.) (जीएसटी अतिरिक्त): खतौली3350, सिहोरा 3180, बुंदकी 3215, बुढ़ाना 3290,

हापुड़
गुड़-चीनी: चीनी हाजिर 3550/3650, गुड़ (प्रति 40 किलो) बाल्टी 880/890, तिलहन: सरसों (42 प्रतिशत कंडी.) 4350, खल: सरसों 2250/2350, बिनौला 2400/2500, चना छिलका 1950/2000,

जयपुर
अनाज: चावल डीबी 5600/5700, गेहूं (मिल) 2140/2150, मक्की 2050/2100, बाजरा 1820/1825, जौ 1800/1850, ग्वार लूज 3800/3825, ज्वार कैटलफीड 2000/2100, तेल-तिलहन: सरसों(मिल पहुंच) 4590/4600,

श्रीगंगानगर
गेहूं (ढेरी) 2000/2050, ग्वार 3750/3800, जौ 2040/2150,

जोधपुर
गेहूं 2000/2100, जौ 1750/1800, पोपकोन मक्की 4400/4500, ग्वार डिलीवरी (ऑलपेड) 3950/4000, ग्वारगम 7300/7400, बाजरा (गुजरात) 1900/1925, बाजरा (जयपुर) 1890/1900, चना 4000/4100, काबली चना 4800/6000, मूंग 6000/6100,

खन्ना
जीएसटी अतिरिक्त (प्रति क्विं.): राइसब्रान (खाद्य)(प्रति प्वाइंट)127, राइसब्रान (अखाद्य) 124, खल सरसों 2080, डीओसी: राइसब्रान बैच सफेद 1250, लाल 1250, कंटीन्यूअस 1300,

लुधियाना
दाल-दलहन: राजमां चित्रा 7500/8000, अरहर दाल 7900/8400, उड़द साबुत 7500/8300, उड़द धोया 9500/10500, छिलका 9000/10000, दाल मसूर 5500/5800, चनादाल 5400/5600,

अमृतसर
चावल: बासमती (1121 नं.) स्टीम 6500/6600, सेला 5700/5800, शरबती साधारण सेला 3800/3900, शरबती स्टीम 4300/4400,चावल 1509 सेला 5200/5300, धान: शरबती 2100/2150,

बठिंडा
रुई (प्रति मन): जे-34 पंजाब नई 3925/3965, हरियाणा 3920/3940, राजस्थान 3860/3950, खल (प्रति क्विं.): बिनौला 2300/2400, सरसों खल 2150/2160,

फाजिल्का
गेहूं 2140/2150, सरसों 4350/4400 रुई (प्रति मन): (जे-34) 3900/3950,कपास देशी 4850/4950, कपास नरमा (क्विं.) 5000/5100, बिनौला (टैक्सपेड): खल 2300/2400,

जालंधर
गेहूं दड़ा 2120/2130, चावल परमल कच्चा 2450/2500, से ला 2375/2400, मक्की यूपी 2225/2300, बिहार 2350/2360, दाल उड़द छिलका 9000/10500, चना देशी 5250/5350, दाल चना 5400/5500, काबली चना 5000/6000, राजमां चित्रा पुणे 7000/8600, चीन 7400/8000,

करनाल
गेहूं दड़ा 2140/2150, बासमती चावल 6600/6700, धान 1121 नं. 2850/2950, पूसा 1509 धान 2550/2650, शरबती धान 2150/2200, सेला (1509 नं.) चावल 5300/5400, स्टीम 6400/6500,

हिसार
ग्वार 3800/3850, सरसों 4100/4150, गेहूं 2140/2145, नरमा कपास 5000/5100

जींद
जीएसटी अतिरिक्त: गेहूं 2100/2150, आटा (प्रति 44 किलो) 1070/1090, मैदा 1175/1190, देशी घी (एक ली/जार) 370/470, रिफाइंड (टीन) 1385/1400,

भिवानी
जीएसटी अतिरिक्त: सरसों 4050/4100, खल बिनौला मोटी 2200/2300, बिनौला 2400/3100, सरसों तेल 8750/8800, गेहूं 2100/2200, ग्वार 3750/3800, बाजरा 1800/1900 *एनएनएस*

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 250

निजी डेटा का संरक्षण

कैबिनेट ने निजी डेटा संरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसे मौजूदा सत्र में ही संसद में पेश किया जाएगा। यह पहला ऐसा कानून है जो व्यक्तिगत या निजी डेटा के संरक्षण के लिए ठोस सिद्धांत सामने रखता है। यह निजता के मूलभूत अधिकार को संहिताबद्ध करने का भी पहला मामला है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 के एक निर्णय में इस अधिकार की पुष्टि की थी। यह ऐसे सिद्धांत सामने रखता है जिनके आधार पर डेटा के व्यक्तिगत, संवेदनशील या अहम होने का निर्धारण किया जाएगा। यह उस प्रक्रिया के बारे में भी बताता है जिसके द्वारा ऐसा डेटा सहमति से हासिल, भंडारित या प्रसंस्कृत किया जाएगा। बहरहाल, विधेयक कोई व्यापक निजता कानून नहीं है क्योंकि यह कई बिंदुओं को अधूरा छोड़ देता है। नागरिकों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने के पहले इसमें व्यापक संशोधन की आवश्यकता हो सकती है। ऐसे में इसे पारित करने के पहले अच्छी तरह जांच-परख की आवश्यकता है। इसका शुरुआती मसौदा गत वर्ष जुलाई में न्यायमूर्ति बी एन श्रीकृष्ण की अध्यक्षता वाली समिति ने पेश किया था। जानकारी के मुताबिक यह देरी तमाम संशोधनों और अंतर मंत्रालयीन मशविरों की वजह से हुई। जो मसौदा संसद में पेश किया जाना है वह सार्वजनिक भी नहीं है।

इतना ही नहीं मशविरा प्रक्रिया भी अस्वाभाविक रूप से अस्पष्ट रही। इलेक्ट्रॉनिक ऐंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने तमाम अनुरोधों और संसद में सवाल उठने के बावजूद किसी भी टिप्पणी को सार्वजनिक करने से मना कर दिया है। इसकी वजह से अन्य लोगों के साथ-साथ स्वयं न्यायमूर्ति श्रीकृष्ण के साथ भी विवाद हुआ। इन सबका कहना था कि अब मशविरा प्रक्रिया समाप्त होने के बाद टिप्पणियों को जारी किया जाना चाहिए। समिति के मसौदे में कहा गया है कि संवेदनशील निजी डेटा केवल उन्हीं सर्वर में भंडारित और प्रसंस्कृत किया जाना चाहिए जो देश में स्थित हों। इसमें डेटा हासिल करते वक्त सहमति प्राप्त करने की प्रक्रिया का भी स्पष्ट उल्लेख है।

बहरहाल, विधेयक देशव्यापी निगरानी और कई उद्देश्यों के लिए बिना कारण बताए डेटा संग्रहीत करने की बात करता है। यह बचाव, अनुसंधान, जांच, अभियोजना या किसी अन्य विधिक उल्लंघन के मामले में निजी डेटा के प्रसंस्करण की इजाजत देता है। निगरानी से समुचित विधिक बचाव के अभाव में और नेत्र जैसे व्यापक निगरानी ढांचे के बीच इसे एक बड़ी कमी माना जा सकता है।

जो मसौदा पेश किया जाना है वह सरकार को तमाम गैर-व्यक्तिगत डेटा तक पहुंच का अधिकार देता है। भले ही उक्त डेटा निजी संस्थान द्वारा जुटाया गया हो। गैर-व्यक्तिगत डेटा की परिभाषा व्यापक है। इसमें ऐसा डेटा भी शामिल हो सकता है जहां लोगों के नाम हटा दिए गए हों। ऐसे गैर-व्यक्तिगत डेटा तक पहुंच के तमाम तरीके हैं। खासतौर पर आधार, बैंक खातों और अन्य संवेदनशील जानकारी के बाद। ऐसे गैर व्यक्तिगत डेटा का इस्तेमाल चुनावों के दौरान मतदाताओं को अनैतिक रूप से प्रभावित करने में किया जा सकता है। मसौदा सोशल मीडिया नेटवर्क से भी कहता है कि वे उपभोक्ताओं की पहचान सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएं। यदि इसका इस्तेमाल सरकार के आलोचकों को निशाना बनाने के लिए किया गया तो देश के सोशल मीडिया जगत में अभिव्यक्ति की आजादी को काफी क्षति पहुंचेगी।

इन तमाम कमियों और अंतराल के बावजूद व्यक्तिगत डेटा संरक्षण की दिशा में यह पहला बुनियादी ढांचा अहम है। ऐसे कानून के अभाव में सरकार के अंगों और निजी क्षेत्र के लिए बिना सहमति के लोगों का डेटा जुटाना आसान है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद दो साल में हमने ऐसा देखा है। परंतु कानून बनाने वालों को विधेयक की सावधानी से परीक्षा करनी चाहिए और उचित प्रश्न उठाने चाहिए ताकि कानून की कमियों को दूर किया जा सके।

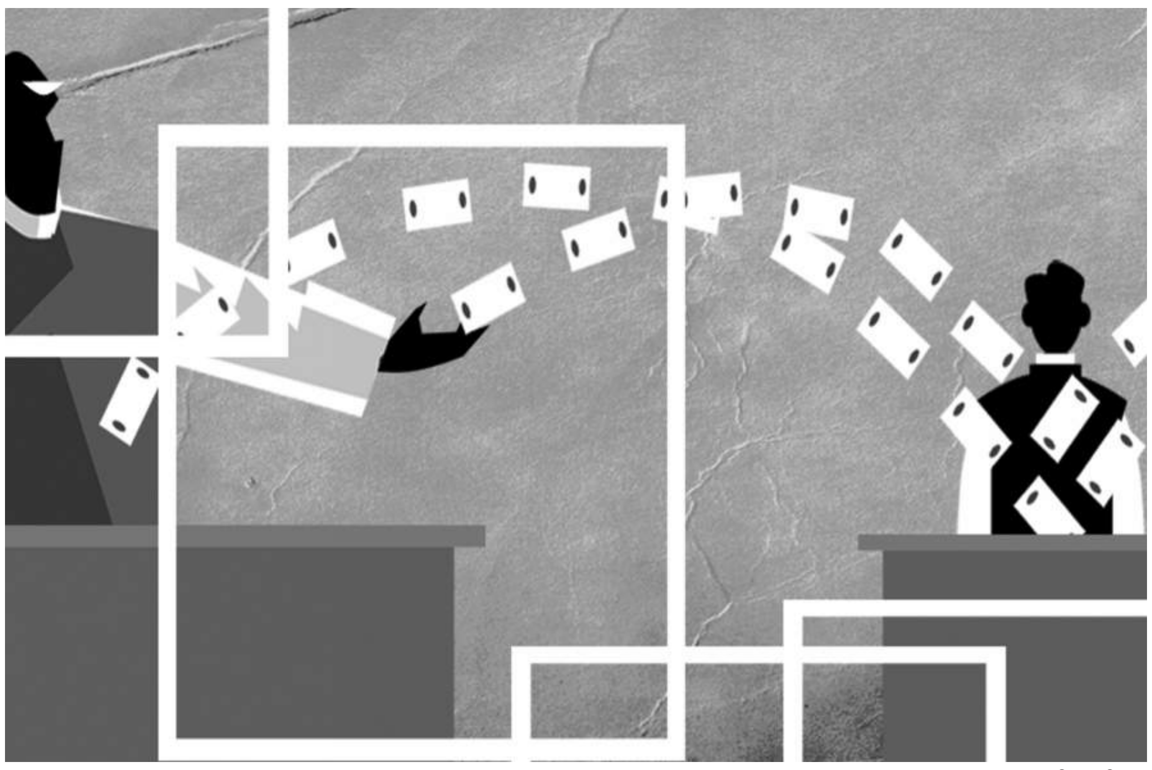

विनय सिन्हा

छिपे हुए आंतरिक संबंध वृद्धि को कर रहे प्रभावित

राज्यों के बजट पर पड़ रहे राजकोषीय दबाव की प्रकृति चक्रीय अधिक है। वहीं कमजोर आयात के कारण बॉन्ड प्रतिफल बढ़ रहा है। विस्तार से जानकारी प्रदान कर रहे हैं **नीलकंठ मिश्रा**

आर्थिक व्यवस्था एक जटिल व्यवस्था है जहां कई अंत:संबंध होते हैं जिन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। जबकि इनका आर्थिक गति और आर्थिक चक्र पर गहरा असर होता है।

राज्य के व्यय से शुरुआत करें तो आम धारणा में सरकार से तात्पर्य केंद्र की सरकार से होता है। जब कंपनियां भुगतान में देरी की शिकायत करती हैं तो हर कोई केंद्र की तरफ देखता है। बहरहाल, विशुद्ध आधार पर देखा जाए तो राज्य मिलकर केंद्र की तुलना में 90 फीसदी अधिक व्यय करते हैं। अपने व्यय के मामले में उन्हें केंद्र की तुलना में अधिक विवेकाधिकार भी हासिल हैं। उदाहरण के लिए केंद्र के व्यय का करीब चौथाई हिस्सा ब्याज भुगतान में जाता है। उसका पांचवां हिस्सा वेतन और पेंशन में जाता है जिसे टाला नहीं जा सकता। रक्षा व्यय, राज्यों को हस्तांतरण और सब्सिडी को इसमें जोड़ें तो केंद्र के व्यय का तीन चौथाई हिस्सा इसमें जाता है।

राज्य सरकार के भुगतान को लंबित करने की गुंजाइश अधिक होती है। राज्यों के कुल बजट को देखें तो इस वर्ष उनके पास 38 लाख करोड़ रुपये की राशि व्यय करने को है। यह पिछले वर्ष के व्यय से 19 फीसदी अधिक और जीडीपी की हिस्सेदारी के रूप में करीब एक फीसदी ज्यादा है। पूंजीगत व्यय के गत वर्ष की तुलना में 21 फीसदी बढ़कर 6.3 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। परंतु इन आंकड़ों में संशोधन के बाद काफी कमी आ सकती है। राज्य अक्सर बजट में तय व्यय एवं प्राप्ति के लक्ष्य से चूक जाते हैं। क्रियान्वयन की चुनौतियां भी हैं। हाल के वर्षों में राज्यों की उधारी तय लक्ष्य से कम रही है। इन वर्षों में प्राप्तियों में कमी इसलिए रही क्योंकि केंद्र से होने वाला कर स्थानांतरण बजट अनुमान से कम रहा। इस वर्ष हालात अधिक खराब हो सकते हैं। हमारा अनुमान है कि कुल व्यय वृद्धि सालाना आधार पर 7 फीसदी तक फिसल सकता है।

महालेखा परीक्षक (सीजीए) द्वारा केंद्र सरकार के मासिक आंकड़े पेश किए जाने के साथ ही विश्लेषक केंद्रीय कर में फिसलन का परीक्षण करते हैं। इसके साथ ही वे केंद्रीय घाटे और व्यय पर इसके प्रभाव का आकलन भी करते हैं। बहरहाल, यह देखते हुए कि केंद्रीय कर का 42 फीसदी स्वत: राज्यों को हस्तांतरित हो जाता है और राज्यों के कुल व्यय का 40 फीसदी हिस्सा इन्हीं से बनता है, कहा जा सकता है कि राज्यों पर इसका काफी असर है। राज्यों के पास अपने राजकोषीय घाटा लक्ष्य को लेकर कोई लचीलापन नहीं है। परंतु इसका आकलन मुश्किल है क्योंकि सीजीए की वेबसाइट पर सभी राज्यों के मासिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। चूंकि धीमी अर्थव्यवस्था का असर राज्यों की प्राप्तियों पर भी पड़ता है इसलिए, जिन राज्यों के राजकोषीय घाटे की सीमा 3 फीसदी के आसपास है उन्हें व्यय में कटौती करनी होगी।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यय का मुद्दा हालात को और खराब कर सकता है। जब जीएसटी की शुरुआत हुई, राज्यों से वादा किया गया था कि पांच वर्ष तक सालाना 14 फीसदी की दर से राजस्व वृद्धि होगी। यह भी कहा गया था कि संग्रह में किसी भी कमी की भरपाई केंद्र सरकार द्वारा जुटाए जा रहे क्षतिपूर्ति उपकर के माध्यम से की जाएगी। यह उपकर कोयला, कारों, तंबाकू और कुछ पेय पदार्थों पर लगे अधिभार से आती। गत वर्ष तक राज्यों को जीएसटी का लाभ मिल रहा था क्योंकि धीमी होती अर्थव्यवस्था के बावजूद उनका राजस्व अधिक प्रभावित नहीं हुआ। बल्कि जीएसटी में समाहित करों के साथ उनकी स्थिति सुधरी। परंतु इस वर्ष जीएसटी कर संग्रह में 14 फीसदी वृद्धि के अनुमान को चुनौती मिल सकती है। इसलिए क्योंकि जीएसटी संग्रह इतना कमजोर रहा है कि क्षतिपूर्ति उपकर की मात्रा इतनी नहीं होगी कि उसे राज्यों को सौंपा जा सके। कोयले में मंदी और वाहनों की मांग में कमी ने इस उपकर संग्रह पर असर डाला है।

यदि केंद्र इस वर्ष भरपाई नहीं कर पाता है और अगले वर्ष भी ऐसा होता है तो प्राप्तियों में जो कमी आएगी उसका असर राज्यों के व्यय पर दिखेगा। चूंकि राज्यों ने सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा लागू कर दी है इसलिए उनकी व्यय प्रतिबद्धता में भी भारी इजाफा हुआ है। उनका पेंशन बिल पहले ही कुल व्यय का 10 फीसदी है। ऐसे में व्यय में कटौती के लिए विवेकाधीन पूंजीगत व्यय में कमी की जा सकती है। शायद कंपनियां जिस लंबित भुगतान की बात कर रही हैं वह इसी वजह से है। बीते कुछ वर्षों के दौरान राज्यों के समेकित पूंजीगत व्यय का महत्त्व बढ़ा है। इसने कुछ हद तक निजी घरेलू पूंजीगत व्यय में आई कमी की भरपाई की है। राज्य सरकारों के पूंजीगत व्यय में कटौती का नकारात्मक असर भविष्य में आर्थिक वृद्धि पर पड़ सकता है। इससे हालात और बिगड़ेंगे।

दूसरा महत्त्वपूर्ण अंतर्संबंध है ब्याज दरों पर मंदी का प्रभाव। अर्थव्यवस्था में धीमापन आने के साथ ही आयात और वाणिज्यिक वस्तुओं के व्यापार में कमी आई है। चूंकि भारत का सेवा व्यापार 130 अरब डॉलर का है और बीते दो महीनों में उसका वार्षिक वस्तु व्यापार घाटा 125 अरब डॉलर है, तो इससे यही संकेत निकलता है कि देश चालू खाते के अधिशेष में है। यह अस्थायी हो सकता है क्योंकि सोने का आयात सामान्य स्तर से नीचे है। परंतु इस अवधि में निरंतर पूंजीगत आवक के कारण भारत भुगतान संतुलन अधिशेष की स्थिति में भी रहा। केंद्रीय बैंक द्वारा इसके समायोजन के लिए हस्तक्षेप करने के बाद देश का आरक्षित भंडार दो महीने में 15 अरब डॉलर बढ़ा।

दिलचस्प बात यह है कि स्थानीय बॉन्ड कारोबारी इसे सरकारी बॉन्ड प्रतिफल में इजाफे की वजह मानते हैं। तर्क यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक खुले बाजार में सरकारी बॉन्ड की खरीद के जरिये अथवा मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप के जरिये टिकाऊ नकदी डालता है। मुद्रा बाजार में वह डॉलर खरीदता और रुपये की बिक्री करता है। यदि डॉलर की खपत की दर इतनी अधिक है तो उसे सरकारी बॉन्ड खरीदने की आवश्यकता नहीं। इससे सरकारी बॉन्ड की मांग में कमी की स्थिति बनती है। यही कारण है कि कमजोर आयात और कमजोर अर्थव्यवस्था होने पर भी सरकारी बॉन्ड के लिए प्रभावी ब्याज दर में कमी नहीं आ रही।

बाजार प्रतिभागियों और नीति निर्माताओं के लिए यह आवश्यक है कि वे अर्थव्यवस्था के इन अंतर्संबंधों की पड़ताल करें और आर्थिक गति पर इनके प्रभाव को सीमित करने के लिए कदम उठाएं।

भारतीय मीडिया फर्मों के बढ़ते आकार से कारोबार विस्तार

मीडिया मंत्र
वनिता कोहली-खांडेकर

सोनी वायकॉम18 का अधिग्रहण करने जा रही है और सुभाष चंद्रा ने ज़ी एंटरटेनमेंट के चेयरमैन से इस्तीफा दे दिया। आखिर भारत के 1.67 लाख करोड़ रुपये के आकार वाले मीडिया एवं मनोरंजन उद्योग में गत दिनों हुए इन घटनाक्रम के क्या मायने हैं?

इसका मतलब है कि मीडिया का जिस तरह से वितरण एवं उपभोग होता रहा है उसमें बुनियादी बदलाव हो रहे हैं और वे कॉर्पोरेट ढांचे में ढलते जा रहे हैं। मीडिया, दूरसंचार एवं तकनीक का सम्मिलन पूरा हो चुका है और बाजार विकास के इस दौर में आकार ही सबसे अहम तत्त्व है। वर्ष 2017 में रुपर्ट मर्डोक ने ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी फॉक्स की अधिकांश मनोरंजन परिसंपत्तियां 69 अरब डॉलर वाली वॉल्ट डिज्नी कंपनी को बेच दी थीं। इस तरह सेंचुरी फॉक्स ने उस कारोबार से अपना नियंत्रण खत्म कर लिया जिसे उसने छह दशकों में शिद्दत से खड़ा किया था। पर्यवेक्षकों का कहना है कि यह सौदा इस अहसास का नतीजा था कि मनोरंजन बाजार नए सिरे से गठित हो रहा है, लिहाजा 29 अरब डॉलर से भी कम राजस्व वाली सेंचुरी फॉक्स अपनी प्रासंगिकता के लिए जद्दोजहद करती रह जाएगी। नए प्रतिस्पर्द्धी बेहद बड़े थे और उनके पास कारोबार में बने रहने की अधिक क्षमता थी। इनमें ऐपल (260 अरब डॉलर), एमेजॉन (233 अरब डॉलर), एटीऐंडटी (184 अरब डॉलर) और गूगल एवं यूट्यूब की मूल कंपनी अल्फाबेट (137 अरब डॉलर) शामिल हैं। तकनीक एवं दूरसंचार क्षेत्र की ये दिग्गज कंपनियां दर्शक जुटाने के लिए अरबों खर्च कर रही हैं। इस कारोबार में अभी तक नेटफ्लिक्स (16 अरब डॉलर) का ही दबदबा रहा है। केबल कनेक्शन को तिलांजलि देने (कॉर्ड-कटिंग) से भुगतान वाले टीवी कारोबार में मार्जिन बढ़ा जिससे मुनाफे का नीचे गिरना लाजिमी ही था। अधिकतर विश्लेषकों ने इस बिक्री की तारीफ करते हुए कहा था कि मर्डोक ने फॉक्स को भविष्य के झटके झेलने लायक बना दिया।

हालांकि इंटरनेट एवं मांग-आधारित मनोरंजन एक वैश्विक बाजार में संचालित होता है। वैसे भारत मीडिया क्षेत्र में कॉर्पोरेट परिपक्वता या उन्नत पारिस्थितिकी के लिहाज से बाकी दुनिया से दशकों पीछे है। यहां पर इंटरनेट ने वर्ष 1995 में दस्तक दी थी। लेकिन बाजार वृद्धि के कई चरणों को धता बताते हुए यह अलग ढंग से बढ़ा और आज दुनिया भर में वीडियो उपभोग करने वाले अग्रणी देशों में शामिल है। केवल ऑनलाइन ही नहीं बल्कि टीवी पर भी ऐसा ही हो रहा है।

83.6 करोड़ से भी अधिक भारतीय प्रतिदिन परंपरागत टीवी सेट पर चार घंटे से थोड़ा ही कम वक्त बिताते हैं। यह संख्या लगातार बढ़ रही है। और उनमें से 60 करोड़ से अधिक लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ड्रामा सीरीज, फिल्में एवं उपभोक्ता-सृजित सामग्री देख रहे हैं। कॉमस्कोर के आंकड़े बताते हैं कि गूगल के वीडियो प्लेटफॉर्म यूट्यूब (27.5 करोड़), टाइम्स ग्रुप के एमएक्स प्लेयर (9.5 करोड़) और डिज्नी के हॉटस्टार (9.1 करोड़ उपभोक्ता) सबसे बड़े लाभार्थी हैं। अमेरिका में ओवर-द-टॉप (ओटीटी) उपभोग का बड़ा हिस्सा केबल पाइपों के दम पर चलता है लेकिन भारत में यह दूरसंचार पाइपों के दम पर चलता है। भारत के कुल मीडिया एवं मनोरंजन बाजार का 45 फीसदी हिस्सा टीवी प्रसारण का है। देश के शीर्ष दो मीडिया समूहों- ज़ी एवं स्टार मुख्य रूप से ऐसे टीवी प्रसारक हैं जिनका अन्य मीडिया कारोबार में भी दखल है। डिज्नी के हाथों फॉक्स के अधिग्रहण का मतलब यह था कि स्टार इंडिया का स्वामित्व अब एक ऐसी कंपनी के पास है जो फॉक्स के दोगुने आकार की है। भारत में 90 अरब डॉलर के आकार वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्वामित्व वाली जियो के उभार, 12 अरब डॉलर वाली भारती एयरटेल और गूगल से खतरा है। मोटे तौर पर भारत में 10,000 करोड़ रुपये राजस्व के साथ यह देश की सबसे बड़ी मीडिया फर्मों में से एक है। ऐसे में प्रसारकों के लिए खुद को सशक्त करना तात्कालिक जरूरत हो गया है।

> 83.6 करोड़ से भी अधिक भारतीय प्रतिदिन परंपरागत टीवी सेट पर चार घंटे से थोड़ा ही कम वक्त बिताते हैं। यह संख्या लगातार बढ़ रही है।

पिछले साल के आखिरी दिनों में जब ज़ी को अपना कर्ज कम करने की जरूरत थी तो उसने एक रणनीतिक निवेशक लाने का फैसला किया। कॉमकास्ट (84.5 अरब डॉलर) और सोनी (78 अरब डॉलर) संभावित निवेशक माने जा रहे थे लेकिन लेनदारों से दबाव बढ़ने पर ज़ी एंटरटेनमेंट का 95 फीसदी से भी अधिक हिस्सा वित्तीय निवेशकों के पास चला गया। वे रणनीतिक बिक्री जल्द ही कर सकते हैं। बड़े दर्शक आधार वाला प्रसारक ज़ी किसी भी तकनीकी या दूरसंचार कंपनी के लिए अहम पूंजी साबित होगी।

अपने पोर्टफोलियो को सुधारने के अभियान में लगी सोनी वायकॉम18 में बहुलांश हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने की सोच रही है। ऐसा होने पर सोनी भारत की दूसरी बड़ी मीडिया फर्म बन जाएगी। अगर सब कुछ अनुमान के मुताबिक हुआ तो भारतीय मीडिया जगत की शीर्ष पांच कंपनियां डिज्नी स्टार, सोनी-वायकॉम18, गूगल, टाइम्स ग्रुप और ज़ी एंटरटेनमेंट ही होंगी। ऐसा होने पर दक्षिण भारत का अग्रणी मीडिया समूह कलानिधि मारन का सन टीवी खासा असुरक्षित हो जाएगा।

वैश्विक एवं भारतीय कंपनियों के राजस्व आंकड़ों को देखें तो वे बहुत बड़े हैं। और ये सभी कंपनियां इस समय अपने विस्तार के दौर में हैं। फिलहाल मीडिया एवं मनोरंजन कारोबार महज आकार तक सीमित है। इसमें कई विलय एवं अधिग्रहण होंगे और कुछ अरब डॉलर स्वाहा होंगे। तब जाकर असली विजेता सामने आएंगे।

कानाफूसी

शोक प्रदर्शन

कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाये तो तमिलनाडु के राजनेता आमतौर पर सार्वजनिक कार्यक्रमों में शिरकत के दौरान सफेद कमीज और सफेद रंग की मुंडू (एक किस्म की धोती) अवश्य पहनते हैं। बहरहाल अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) के नेता जिनमें पार्टी समन्वयक और मुख्यमंत्री एडाप्पडी के पलनिस्वामी और उप मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम शामिल थे, गुरुवार को काली पोशाक में अपने कार्यालय पहुंचे। गुरुवार को प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और अन्नाद्रमुक की सर्वेसर्वा रही जे जयललिता की तीसरी पुण्यतिथि थी। कुछ नेत्रियां भी मरीना बीच पर जयललिता की समाधि तक पैदल मार्च में काली साड़ी पहने हुए नजर आईं। नेताओं ने अपने ट्विटर पेज भी काले कर लिए और अम्मा (उन्हें अम्मा कहते थे) की तस्वीर के साथ शोक संदेश लिखे।

बिना फोन के

महत्त्वपूर्ण बैठकों में मोबाइल फोन की वजह से होने वाले व्यवधान को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने गत जून में यह आदेश दिया था कि मंत्रिगण कैबिनेट की बैठकों में मोबाइल नहीं लाएंगे। हाल ही में एक कैबिनेट बैठक के दौरान प्रदेश के एक वरिष्ठ अफसरशाह मोबाइल पर बात करते देखे गए। इससे नाराज मंत्रियों ने मुख्यमंत्री से शिकायत की। इस पर मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि अब प्रदेश के अफसरशाह भी बैठकों में फोन लेकर नहीं आएं।

आपका पक्ष

देश के प्रहरियों की भी सुध लें

हाल में एक हृदयविदारक घटना सामने आई जिसमें छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले में पदस्थ आईटीबीपी के एक जवान ने अपने चार सहकर्मियों की गोली मार कर हत्या कर दी। इस घटना के पीछे के वास्तविक कारणों की जांच अभी जारी है। लेकिन इन घटनाओं को सुरक्षा बलों के सदस्यों में विभिन्न कारणों से व्याप्त अवसाद तनाव एवं कुंठा से होने वाली घटनाओं से जुड़ी कड़ी के रूप में माना जा सकता है। अक्सर सुरक्षा बलों के जवानों की कई प्रकार की समस्याएं सामने आई हैं। आवश्यकता होने पर भी सैनिकों को अवकाश नहीं मिलना आम समस्या है। हाल में सुकमा में हुए नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों के संबंध में एक हैरान करने वाला तथ्य सामने आया है। उक्त हमले के कुछ दिन पूर्व हुए हमले में वह जवान दृढ़ता से लड़ते हुए जांघ में गोली लगने से घायल हो गया था। कुछ दिन उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी होते ही उसे सीधे मोर्चे पर तैनात कर दिया गया। अपने शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति के आधार पर मांगे गए अवकाश के निवेदन को उच्चाधिकारियों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। जवान फिर भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटा। निजी कारणों अथवा अनुशासन के नाम पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कनिष्ठ कर्मचारियों, अधिकारियों को प्रताड़ित करने के कारण हुई आत्महत्या की घटनाएं भी सामने आई हैं जो चिंतनीय है। उक्त घटनाओं की रोकथाम के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। जवानों की ओर से आ रही दिक्कतों से जुड़ी शिकायतों का संज्ञान लिया जाना चाहिए। किसी अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच तटस्थ एवं निष्पक्ष संस्था द्वारा उच्च न्यायालय की देखरेख में की जानी चाहिए। मनोवैज्ञानिक सहायता लिए जाने पर भी विचार किया जा सकता है। सरकार को जवानों के कल्याण पर विचार करना चाहिए।

ऋषभ देव पांडेय, छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में आईटीबीपी के एक जवान ने अपने चार सहकर्मियों की हत्या कर दी थी

भारत पर दूसरे देशों की आबादी का बोझ

सरकार नागरिकता संशोधन विधेयक ला रही है। इसका मकसद पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से शरणार्थी के रूप में भारत आए उन गैर मुस्लिमों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है जिन्हें धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा हो। इससे पहले सरकार राष्ट्रीय नागरिकता पंजीकरण लाई थी जिसे असम में लागू किया गया था। असम में लाखों लोगों को भारतीय नागरिकता नहीं मिल पाई है। ऐसा माना जा रहा है कि ऐसे लोग बांग्लादेश से घुसपैठ कर भारत आए थे। हालांकि सरकार के इस कदम का विपक्षी पार्टियों के नेता विरोध कर रहे हैं। भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है। यहां सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार मिले हैं। ऐसे में किसी विशेष धर्म के लोगों को नकारना उचित प्रतीत नहीं होता है। लेकिन क्या भारत दूसरे देशों से घुसपैठ करने वालों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकता है। अगर भारत में घुसपैठिये नहीं रोके गए तो भारत पर बोझ बढ़ता जाएगा। सरकार को धर्म के आधार पर नागरिकता नहीं देनी चाहिए। अगर सरकार घुसपैठ रोकना चाहती है तो घुसपैठिया किसी भी धर्म का हो उसे देश से बाहर कर देना चाहिए।

अमित कुमार, नई दिल्ली

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

प्याज का भाव 165 रुपये किलो पहुंचा

सरकार ने संसद में बताया कि आयातित प्याज की आवक की शुरुआत 20 जनवरी तक संभव

भाषा
नई दिल्ली, 6 दिसंबर

प्याज के भाव में नरमी का कोई संकेत नहीं दिख रहा है। आयात के जरिये बाजार में प्याज की आपूर्ति बढ़ाने के सरकार के प्रयासों के बावजूद यह शुक्रवार को गोवा और कुछ जगह प्याज 160-165 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया। संसद में सरकार ने बताया कि आयातित प्याज की खेप 20 जनवरी तक देश में आना शुरू हो जाएगी।

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा रखे जाने वाले आंकड़ों के अनुसार देश के ज्यादातर शहरों में, प्याज की खुदरा बाजारों में कीमत 100 रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक था, जबकि प्याज के प्रमुख उत्पादक केंद्र महाराष्ट्र के नाशिक में शुक्रवार को इसकी दर 75 रुपये किलो थी। पणजी (गोवा) में प्याज की खुदरा कीमतें 165 रुपये प्रति किलोग्राम, मायाबंदर (अंडमान) में 160 रुपये किलो और केरल के तिरुवनंतपुरम, कोझिकोड, त्रिशूर और वायनाड में 150 रुपये किलो थी।

मंत्रालय द्वारा विभिन्न शहरों के बारे में जुटाई गई सूचना के अनुसार कोलकाता, चेन्नई तथा केरल एवं तमिलनाडु के कुछ स्थानों पर प्याज का भाव 140 रुपये किलो था जबकि भुवनेश्वर और कटक (ओडिशा) में कीमत 130 रुपये किलो, गुड़गांव (हरियाणा) और मेरठ (उत्तर प्रदेश) में 120 रुपये किलो तथा देश के अधिकांश शहरों में कीमत 100 रुपये किलो रही।

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री दानवे रावसाहेब दादाराव ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा, 'इस बात में कोई शक नहीं कि प्याज की कीमतें बढ़ रही हैं। प्याज की कमी का मुख्य कारण बारिश की वजह से प्याज फसल को होने वाला नुकसान है। देश के प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र में प्याज की अधिकांश फसल बरबाद हो गई है। हालांकि सरकार ने अपने बफर स्टॉक से प्याज की आपूर्ति की है और सरकारी व्यापार एजेंसी एमएमटीसी को प्याज का आयात करने को कहा है जो 20 जनवरी तक पहुंचना चाहिए।'

उन्होंने कहा कि सरकार ने जारी मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए 1.2 लाख टन तक प्याज आयात को मंजूरी दी है। सरकारी स्वामित्व वाली एमएमटीसी को वैश्विक और देश-विशिष्ट वाले आयात निविदाओं के माध्यम से एक लाख टन प्याज आयात करने का निर्देश दिया गया है।

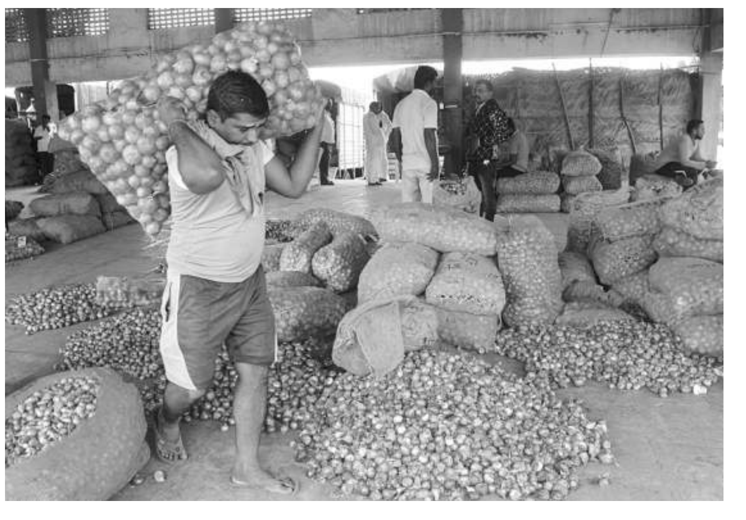

सरकार ने एमएमटीसी के माध्यम से 21,000 टन से अधिक प्याज आयात के लिए अनुबंध किया

गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह की अगुआई में मंत्रियों के एक समूह ने प्याज की कीमत की स्थिति और प्याज के आयात में हुई प्रगति की समीक्षा की। सरकार ने एमएमटीसी के माध्यम से 21,000 टन से अधिक प्याज आयात के लिए अनुबंध किया है। आयातित प्याज के जल्द आगमन को आसान बनाने के लिए इसकी निविदा और धूम्र-उपचार मानदंडों में ढील दी गई है। सरकार ने पहले ही प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। आखिरी बार वर्ष 2015-16 में इसी तरह की स्थितियों में 1,987 टन प्याज आयात किया गया था।

उत्तर प्रदेश में प्याज की राशनिंग

बीएस संवाददाता
लखनऊ, 6 दिसंबर

उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में प्याज की कीमतों में तेजी देख कर योगी सरकार ने एक बार फिर से सरकारी स्तर पर इसकी बिक्री का फैसला किया है। प्याज की सरकारी खरीद को महंगी देखते हुए प्रदेश सरकार ने इसकी राशनिंग करने का भी फैसला किया है। अब सरकारी काउंटरों से एक आदमी केवल दो किलो प्याज ही खरीद सकेगा। अकेले राजधानी लखनऊ में ही प्याज के 50 से ज्यादा काउंटर खोले जाएंगे।

प्याज की सरकारी बिक्री 50 से 60 रुपये किलो के आसपास किए जाने का अनुमान है। अगले हफ्ते से लखनऊ और कुछ अन्य शहरों में सरकारी स्तर पर प्याज की बिक्री शुरू कर दी जाएगी। लखनऊ के साथ ही प्रदेश के कई अन्य शहरों जिनमें इलाहाबाद, कानपुर, आगरा, मेरठ, नोएडा और गाजियाबाद शामिल हैं, में भी प्याज की बिक्री की जाएगी।

प्रदेश सरकार ने प्याज की कीमत 100 रुपये किलो के आसपास पहुंच जाने पर अक्टूबर में इसकी सरकारी बिक्री शुरू की थी। हालांकि प्याज की कीमतों में तेजी थम जाने के बाद इसे बंद कर दिया था। अक्टूबर में प्रदेश सरकार के उद्यान विभाग ने नेफेड से 5 टन प्याज की सरकारी खरीद की थी। उस समय सरकारी केंद्रों पर 50 रुपये किलो प्याज की बिक्री की गई थी। बीते एक हफ्ते से उत्तर प्रदेश में प्याज की कीमतें फिर से बढ़ने लगी है। बुधवार से राजधानी लखनऊ के खुदरा बाजारों में तो प्याज की कीमतें 120 रुपये किलो तक पहुंच गई हैं। प्याज की कीमतों में उछाल को देखते हुए लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने गुरुवार को बैठक कर फौरी तौर पर प्याज बिक्री के 11 काउंटर खुलवाने का फैसला किया है। प्याज की सरकारी बिक्री के काम में मंडी परिषद, कर्मचारी कल्याण निगम और उद्यान विभाग को लगाया गया है। इसके साथ ही प्याज की जमाखोरी पर लगाम लगाने की भी कवायद शुरू की गई है। जमाखोरी रोकने के लिए सभी मंडियों में छापेमारी के लिए कहा गया है। प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों से प्याज की कीमतों पर नजर रखने और कीमत बढ़ने पर रिपोर्ट भेजने को कहा गया है।

उधर प्रदेश के थोक सब्जी मंडियों के आढ़तियों का कहना है कि प्याज की आवक में बीते 15 दिनों में कमी आई है। उनका कहना है कि इस बार स्थानीय किसानों से अधिक प्याज आने की उम्मीद नहीं है। स्थानीय किसानों ने कीमत अच्छी मिलते देख हरा प्याज बेच दिया जिससे स्थानीय फसल कम आएगी।

गेहूं बुआई का रकबा 4.28 प्रतिशत बढ़ा

एजेंसियां
नई दिल्ली, 6 दिसंबर

गेहूं की बुआई रफ्तार पकड़ने लगी है। अब तक इसका रकबा 4.28 फीसदी बढ़कर 202.54 लाख हेक्टेयर तक जा पहुंचा है। कृषि मंत्रालय की तरफ से आज जारी आंकड़ों में गेहूं बुआई के रकबे के बारे में यह जानकारी दी गई। पिछले साल इस समय तक गेहूं की बुआई का रकबा 194.21 लाख हेक्टेयर ही था।

कृषि मंत्रालय के अद्यतन आंकड़ों के मुताबिक, फसल वर्ष 2019-20 के चालू रबी सत्र में पिछले साल के इसी समय के मुकाबले 8.34 लाख हेक्टेयर ज्यादा रकबे में गेहूं की बुआई की गई है। बुआई के रकबे में ज्यादा बढ़ोतरी मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में दर्ज की गई है।

गेहूं रबी सत्र की मुख्य फसल होती है और अक्टूबर से इसकी बुआई शुरू हो जाती है। फसल तैयार होने के बाद अप्रैल से इसकी कटाई शुरू हो जाती है।

चालू रबी सत्र में अभी तक 10.17 लाख हेक्टेयर में धान की भी बुआई की गई है जबकि साल भर पहले यह रकबा 8.42 लाख हेक्टेयर ही था। इस दौरान मोटे अनाज का भी रकबा 35.56 लाख हेक्टेयर तक पहुंचा है। पिछले साल इस समय तक 32.75 लाख हेक्टेयर खेत में मोटे अनाज बोए गए थे।

- **कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार गेहूं का रकबा अबतक 202.54 लाख हेक्टेयर तक पहुंचा**
- **पिछले साल इस समय तक गेहूं की बुआई का रकबा 194.21 लाख हेक्टेयर था**

हालांकि, दलहन बुआई के रकबे में गिरावट देखी जा रही है। पिछले साल इस समय तक 111.90 लाख हेक्टेयर में दलहन फसलें बोई गई थीं लेकिन इस सत्र में 105.16 लाख हेक्टेयर में ही इनकी बुआई हुई है। तिलहनों की बुआई का रकबा भी पहले के 66.10 लाख हेक्टेयर के मुकाबले चालू रबी सत्र में 65.05 लाख हेक्टेयर ही है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार रबी सत्र की सभी फसलों की बुआई का कुल रकबा 418.47 लाख हेक्टेयर तक जा पहुंचा है जो साल भर पहले की समान अवधि में 413.36 लाख हेक्टेयर था।

अंतरराष्ट्रीय और घरेलू भाव

As on Dec 6	International Price	International %Chg#	Domestic Price	Domestic %Chg#
METALS ($/tonne)				
Aluminium	1,756.0	-0.3	1,895.8	-3.6
Copper	5,855.0	1.2	6,235.1	0.5
Nickel	13,165.0	-24.8	14,183.4	-21.7
Lead	1,893.0	-7.0	2,134.5	4.2
Tin	16,900.0	-1.0	17,694.1	-3.8
Zinc	2,255.0	-2.5	2,597.9	-0.3
Gold ($/ounce)	1,476.0*	-2.0	1,660.7	0.3
Silver ($/ounce)	17.0*	-6.8	19.3	-5.4
ENERGY				
Crude Oil ($/bbl)	64.0*	2.9	63.9	6.5
Natural Gas ($/mmBtu)	2.4*	-3.6	2.4	-2.4
AGRI COMMODITIES ($/tonne)				
Wheat	185.8	12.7	299.1	6.1
Maize	183.1*	3.1	316.8	6.9
Sugar	348.0*	14.4	484.6	-1.7
Palm oil	677.5	27.2	1,074.3	23.7
Rubber	1,597.9*	3.5	1,839.6	-5.7
Coffee Robusta	1,406.0*	10.5	1,888.8	-7.8
Cotton	1,400.2	8.1	1,572.0	-1.3

* As on Dec 06, 19 1800 hrs IST, # Change Over 3 Months, Conversion rate 1 USD = 71.2& 1 Ounce = 31.1032316 grams.

Notes:
1) International metals, Indian basket crude, Malaysia Palm oil, Wheat LIFFE and Coffee Karnataka robusta pertains to previous days price. 2) International metal are LME Spot prices and domestic metal are Mumbai local spot prices except for Steel. 3) International Crude oil is Brent crude and Domestic Crude oil is Indian basket. 4) International Natural gas is Nymex near month future & domestic natural gas is MCX near month futures. 5) International Wheat, White sugar & Coffee Robusta are LIFF E future prices of near month contract. 6) International Maize is MATIF near month future, Rubber is Tokyo-TOCOM near month future and Palm oil is Malaysia FOB spot price. 7) Domestic Wheat & Maize are NCDEX future prices of near month contract, Palm oil & Rubber are NCDEX spot prices. 8) Domestic Coffee is Karnataka robusta and Sugar is M30 Mumbai local spot price. 9) International cotton is Cotton no.2-NYBOT near month future & domestic cotton is MCX Future prices near month tures.

Bloomberg chartMaker

Compiled by BS Research Bureau

एमसीएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	21.7	12161
Oil and Oilseeds	339.7	65873
Spices	1.2	14
Metal(Dec 05)		
Metal- non ferrous	5484.8	60399
Metal- precious	8156.6	456
Oil and gas(Dec 05)		
Gas	2921.3	36056
Oil	16754.4	2549

एनसीडीईएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	111.3	112534
Grains	220.5	102680
Oil and Oilseeds	841.3	495825
Others	163.2	68290
Pulses	120.3	60925
Spices	89.2	32790

एमसीएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Gainers (* % Change)		
Cardamom (Dec 13)	3080.2	2.4
Crude Palm Oil (Dec 31)	706.2	2.0
Natural Gas (Dec 26)	174.6	1.9
Nickel (Dec 31)	983.6	1.4
Silver Mini (Feb 28)	44634.0	0.4
Silver Micro (Feb 28)	44630.0	0.4
Losers (* % Change)		
Zinc (Dec 31)	182.8	-0.7
Mentha Oil (Dec 31)	1291.0	-0.7
Zinc Mini (Dec 31)	183.1	-0.6
Crude Oil (Dec 18)	4161.0	-0.5
Crude Oil Mumbai (Dec 18)	4161.0	-0.5
Aluminium (Dec 31)	132.6	-0.5

एनसीडीईएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Gainers (* % Change)		
Jeera Unjha (Dec 20)	16235.0	2.3
CottonSeed Oil-Akola (Dec 20)	1964.0	2.0
Ref Soy Oil-IDR-2016 (Dec 20)	845.8	1.6
CastorSeed New-Disa (Dec 20)	4168.0	1.4
GuarGum 5T-Jodhpur (Dec 20)	7335.0	0.5
Turmeric Nizamabad (Dec 20)	5678.0	0.5
Chana-Bikaner (Dec 20)	4440.0	0.5
Soyabean Indore (Dec 20)	4114.0	0.4
Shankar Kapas-Rajkot (Apr 30)	1074.0	0.3
Guar Seed 10 (Dec 20)	4050.0	0.1
Losers (* % Change)		
Coriander-Kota (Dec 20)	6722.0	-1.0
Mustard Seed Rape Oil (Dec 20)	4389.0	-0.1

एमसीएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Cardamom Vandanmedu (Dec 13)	3080.2	6.3
Kapas Surendranagar (Feb 28)	1043.0	3.4
Cotton-Rajkot (Dec 31)	19030.0	2.3
Gold Petal-Mumbai (Dec 31)	3879.0	1.7
Silver Micro-Ahemd (Feb 28)	44630.0	1.3
Silver Ahm (Dec 05)	44333.0	0.6
Discount over spot price (In %)		
Menthol Oil Chandaus (Dec 31)	1291.0	-8.1
Aluminium Mum (Dec 31)	132.6	-6.3
Alumini-Mumbai (Dec 31)	132.6	-6.3
Copper Mum (Dec 31)	430.6	-4.2
Lead Mum (Dec 31)	152.6	-2.2
Lead Min Mumbai (Dec 31)	152.6	-2.2

एनसीडीईएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Paddy-Basmati-Karnal (Dec 20)	3158.0	1.9
Maize-Sangli (Dec 20)	2032.0	1.5
Soy Bean Indore (Dec 20)	4114.0	0.4
Barley Jaipur (Dec 20)	2124.5	0.1
29 mm Cotton-Rajkot (Dec 20)	18540.0	0.0
Discount over spot price (In %)		
Turmeric Nizamabad (Dec 20)	5678.0	-3.8
Coriander-Kota (Dec 20)	6722.0	-3.6
Crude Palm Oil Kandl (Dec 31)	694.8	-2.4
Guar Gum 5 MT-Jodhpu (Dec 20)	7335.0	-1.2
Jeera Unjha (Dec 20)	16235.0	-1.1
Moong-Merta City (Dec 20)	6700.0	-0.7

कल का हाजिर भाव

औद्योगिक

Metals	Mumbai	
Aluminium utensil scrap /kg	95	(98)
Aluminium ingots /kg	135	(135)
Brass sheet cutting /kg	312	(312)
Brass utensil scraps/kg	295	(295)
Copper heavy scrap /kg	412	(411)
Copper utensil scraps/kg	390	(389)
Copper wire bar /kg	444	(444)
Lead ingots /kg	152	(152)
Nickel Cathodes /kg	1010	(1010)
Tin slabs /kg	1260	(1255)
Zinc slabs /kg	185	(185)

Source:Bombay Metal Exchange

Cotton	Mumbai	
Bengal Deshi /Qtl	10714	(10714)
DCH - 32 /Qtl	11417	(11360)
Jaydhar /Qtl	10011	(10011)
Shankar- 6 /Qtl	11220	(11220)

Source:Cotton Association of India

Oil	Mumbai	
Castor FSG /10kg	890	(867)
Castor Comm /10kg	880	(857)
Ricebran oil/10kg	760	(760)
Groundnut oil /10kg	1035	(1030)
Linseed oil /10kg	845	(845)
Karanji /10kg	760	(760)
Palm oil /10kg	783	(770)
Sunflower exp ref /10kg	838	(835)
Sunflower oil exp /10kg	795	(790)
Soyabean ref / 10kg	830	(820)

Source:Bombay Commodity Exchange

सॉफ्ट

Sugar	Mumbai	
Mumbai M-30 /Qtl	3330-3572	(3332-3572)

Source:Bombay Sugar Merchants Association

ऊर्जा

Crude Brent-$/Barrel		
NYSE Crude	58.4	(58.43)
Brent Crude (UK)	64.26	(64.17)
Brent Crude (WTI)	58.43	(58.43)
NYSE Natural Gas-$/Mmbtu	2.42	(2.43)
Furnace/ 180 Cst &/bbl	246.11	(244.42)
Naptha spot /Rs/MT	45170	(45170)
LSHS spot/ M.T.	36150	(36150)
Furnace Oil spot/ K.L.	33950	(33950)

Source:Petroleum Bazaar.com

सर्राफा

Gold	Mumbai	
Standard (99.50 Purity) /10 gms	38022	(38028)
Pure (99.90 Purity) /10 gms	38175	(38181)
Silver.999/ kg	44115	(43980)

Source:India Bullion & Jewellers Association

@SPOT PRICE(MCX, NCDEX & ICEX)

Commodity	Unit	PClose	Price (₹.) Close
29 mm Cotton-Rajkot (N)	1 B	18491.55	18533.00
Alumini-Mumbai (M)	1 K	138.65	141.45
Bajra-Delhi (N)	1 Q	1900.00	1920.00
Barley Jaipur (N)	1 Q	2119.30	2121.90
Brass-Jamnagar (M)	1 K	303.40	303.40
Cardamom-Vand. (I)	1 K	2900.00	2983.00
Castor Seed Disa (N)	1 Q	4121.45	4156.25
Castor Seed-Kadi (N)	X	4075.00	4100.00
Chana Bikaner (N)	1 Q	4305.15	4304.00
Chana Delhi (N)	1 Q	4459.40	4490.45
Chana-Akola (N)	X	4400.00	4412.50
Coriander-Gondal (N)	X	6700.00	6700.00
Coriander-Jaipur (N)	X	6848.75	6931.10
Coriander-Kota (N)	1 Q	6936.55	6971.10
Cotton Seed Oilck Ak (N)	1 Q	1987.80	1987.85
Cotton Seed Oilck Ka (N)	1 Q	1958.35	1965.20
Cotton-Kadi (N)	1 B	18429.40	18477.20
CPO-Kandla (M)	10 K	689.30	703.90
Crude Palm Oil Kandl (N)	10 K	692.05	711.65
Diamond 0.3 - Surat (I)	1 CT	883.60	882.70
Diamond 0.5-Surat (I)	1 CT	1538.05	1539.85
Diamond 1-Surat (I)	1 CT	3469.20	3460.55
Gold Ahm (M)	10 G	38042.00	38032.00
Gold Guinea-Ahmedaba (M)	8 G	30556.00	30548.00
Gold Petal-Mumbai (M)	1 G	3819.00	3814.00
Guar Gum 5 MT-Jodhpu (N)	X	7190.45	7420.70
Guar Seed 10 MT-Jodh (N)	1 Q	3900.00	3998.65
Guarseed-Jodhpur (I)	1 Q	3900.00	3950.00
Gur Muzaffar Nagar (N)	40 K	1014.05	1014.05
Isabgulseed-Unjha (I)	1 K	93.65	93.05
Jeera Jodhpur-Jodhpu (N)	X	16850.00	16950.00
Jeera Unjha (N)	1 Q	16237.50	16412.50
Kapas Kadi-Kadi (N)	X	1009.40	1009.20
Kapas-Rajkot (N)	X	1003.15	1005.10
Lead Mum (M)	1 K	158.40	156.00
Maize Kharif-Nizamab (N)	X	1920.65	1900.00
Maize Rabi-Gulabbagh (N)	1	2250.15	2256.65
Maize-Erode (N)	X	2044.60	2059.50
Maize-Feed/Ind-Delhi (N)	1 Q	2121.25	2150.00
Maize-Sangli (N)	X	2010.90	2002.50
Moong-Merta City (N)	1 Q	6805.55	6745.00
Mustardseed Alwar (N)	20 K	4540.00	4585.05
Nickel Mumbai (M)	1 K	994.00	1002.40
Paddy-Basmati-Karnal (N)	X	3150.00	3100.00
Paddy-Basmati-Karnal (I)	1 Q	3186.00	3210.00
Pepper-Ernakulam (I)	1 K	350.00	350.00
Pepper-Kochi (N)	1 Q	35000.00	34792.85
Rape mustards-Patan (I)	20 K	797.00	797.00
Rapeseed Must.Seed (N)	X	2088.50	2083.05
RBD Palm Olein Kakin (N)	10 K	754.65	765.00
Ref Soya Oil Indore (N)	10 K	829.40	843.30
Ref Soya Oil Mum (N)	10 K	822.55	830.00
Ref Soya Oil Nagpur (N)	10 K	834.00	850.00
Rubber-Kochi (N)	1 Q	13000.00	13100.00
Rubber-Kochi/Ernak. (I)	1 Q	13058.00	13100.00
Silver M-Ahemdabad (M)	1 K	43892.00	44062.00
Soy Bean Indore (N)	1 Q	4081.00	4099.00
Soy Bean Kota (N)	1 Q	4018.85	4032.75
Soy Bean Nagpur (N)	1 Q	4090.50	4191.50
Soy Bean-Akola (N)	X	4131.00	4154.00
Soymeal Indore (N)	1 T	33367.00	33500.00
Soyoil-Indore (I)	10 K	826.60	843.00
Steel Long-Ghaziabad (I)	1 T	27810.00	27810.00
Steel Long-MGG (I)	1 T	28900.00	28900.00
Steel Long-Raipur (I)	1 T	25940.00	25940.00
Sugar M Delhi (N)	1 Q	3275.00	3255.00
Sugar M Grade-Kanpur (N)	1 Q	3385.70	3356.95
Sugar M Grade-Kolhap (N)	1 Q	3297.50	3293.75
Sugar M Kolkatta (N)	1 Q	3428.55	3466.65
Sugar M Muzaff (N)	1 Q	3281.65	3285.00
Sugar S-Kolhapur (N)	1 Q	3132.10	3127.10
Turmeric Nizamabad (N)	1 Q	5890.65	5900.00
Wheat Delhi (N)	1 Q	2251.65	2250.00
Wheat Kota (N)	1 Q	2125.00	2124.00
Wheat New Indore (N)	1 Q	2188.75	2200.00
Wheat New Kanpur (N)	1 Q	2072.50	2062.50
Wheat New-Rajkot (N)	1 Q	2192.50	2200.00
Yellow Peas Mum (N)	1 Q	4780.00	4925.00
Zinc Mumbai (M)	1 K	184.60	184.15

* as on Dec 05, 19

(M) MCX ,(N) NCDEX & (I) ICEX Spot prices

जिंस वायदा

DAY SESSION

दिवस सत्र (शुक्रवार)

कृषि जिंस

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Cotton				
Cotton MCX(1 B)				
Dec 31	19070, 19120, 19020, 19030	1573	216	8946
Jan 31	19210, 19250, 19160, 19170	251	46	2560
CottonSeed Oil-Akola NCDEX(1 Q)				
Dec 20	1930, 1969, 1916, 1964	11750	867	29370
Jan 20	1952, 1995, 1939, 1989	28410	1993	53990
Feb 20	1979, 2008, 1960, 2005	3470	306	22770
Mar 20	2000, 2031, 1984, 2023	460	44	2470
Kapas MCX(20 K)				
Apr 30	1071, 1077, 1070, 1073.5	232	40	588
Shankar Kapas-Rajkot NCDEX(20 Kg)				
Apr 30	1070, 1075.5, 1069, 1074	1151	481	3934
Grains				
Barley Jaipur NCDEX(1 Q)				
Apr 20	1670, 1680, 1670, 1680	120	4	640
May 20	1691, 1691, 1691, 1691	50	2	860
Guar Seed 10 NCDEX(1 Qtl)				
Dec 20	4042, 4078, 4016, 4050	13300	1576	25020
Jan 20	4090, 4122, 4062, 4092	39510	4661	69325
Feb 20	4124, 4156, 4102, 4136	1075	182	2210
Oil and Oilseeds				
CastorSeed New-Disa NCDEX(1 Qtl)				
Dec 20	4118, 4200, 4104, 4168	7935	802	24745
Jan 20	4156, 4240, 4140, 4202	10630	1244	25930
Feb 20	4184, 4240, 4178, 4208	210	40	3660
Mar 20	4188, 4214, 4188, 4200	330	47	3230
Crude Palm Oil MCX(10 K)				
Dec 31	695, 708, 695, 706.2	25360	1608	39050
Jan 31	696.6, 707.7, 693.3, 706.1	16840	1001	22770
Feb 28	700, 710.4, 696, 709.2	2520	202	3750
Mentha Oil MCX(1 K)				
Dec 31	1296, 1303, 1288.3, 1291	172.08	368	267.12
Jan 31	1301.4, 1309.6, 1300, 1303.1	22.32	27	35.64
Mustard Seed Rape Oil NCDEX(1 Q)				
Dec 20	4406, 4409, 4381, 4389	8210	488	17010
Jan 20	4430, 4440, 4418, 4421	6280	519	10150
Apr 20	4325, 4358, 4316, 4339	220	18	1430
Ref Soy Oil-IDR-2016 NCDEX(10 Kg)				
Dec 20	844, 850.4, 840.6, 845.8	12205	1056	18560
Jan 20	839.8, 845.2, 837.8, 843	21400	1955	47230
Feb 20	835.8, 841.4, 833, 839.6	3385	234	16465
Mar 20	830, 830, 830, 830	5	1	35
Soyabean Indore NCDEX(1 Q)				
Dec 20	4108, 4144, 4100, 4114	23670	2569	41400
Jan 20	4142, 4190, 4134, 4148	51775	5325	160985
Feb 20	4172, 4204, 4160, 4174	13105	1698	95515
Mar 20	4200, 4224, 4184, 4202	4060	562	29125
Others				
GuarGum 5T-Jodhpur NCDEX(1 Qtl)				
Dec 20	7291, 7392, 7243, 7335	6155	810	11625
Jan 20	7410, 7499, 7340, 7440	15320	2307	55430
Feb 20	7540, 7582, 7451, 7544	565	93	1185
Pulses				
Chana-Bikaner NCDEX(1 Qtl)				
Dec 20	4408, 4454, 4400, 4440	10040	732	21360
Jan 20	4440, 4480, 4435, 4474	16680	1213	36630
Mar 20	4415, 4443, 4400, 4423	290	28	2440
Spices				
Cardamom MCX(1 K)				
Dec 13	3096.9, 3126.9, 3026.9, 3080.2	0.7	7	1.1
Jan 15	2990, 3062.6, 2990, 3060.3	3.2	31	10.4
Coriander-Kota NCDEX(1 Q)				
Dec 20	6792, 6792, 6680, 6722	1320	120	5930
Jan 20	6660, 6660, 6495, 6516	1810	157	6330
Apr 20	6900, 6940, 6870, 6921	400	21	2790
Jeera Unjha NCDEX(1 Q)				
Dec 20	15830, 16280, 15830, 16235	1494	324	1200
Jan 20	15840, 15950, 15770, 15900	1098	309	2169
Mar 20	15800, 15825, 15800, 15800	33	11	186
Apr 20	15800, 15800, 15700, 15700	9	3	15
Turmeric Nizamabad NCDEX(1 Q)				
Dec 20	5630, 5704, 5630, 5678	2125	288	7405
Mar 20	5886, 5938, 5872, 5902	1820	246	5000
Apr 20	5930, 5940, 5898, 5914	135	21	1760

धातु

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Metal- non ferrous				
Aluminium MCX(1 K)				
Dec 31	132.7, 132.95, 131.95, 132	4245	687	10060
Aluminium Mini MCX(1 K)				
Dec 31	132.6, 132.95, 132, 132.1	1885	1557	3425
Jan 31	133.65, 134, 133.25, 133.3	93	70	265
Copper MCX(1 K)				
Dec 31	430.85, 433.95, 430.75, 432.25	14982.5	4889	16175
Jan 31	435.8, 438.5, 435.8, 436.8	260	102	882.5
Lead MCX(1 K)				
Dec 31	152.65, 153.3, 152.5, 152.65	10655	1739	7270
Lead Mini MCX(1 K)				
Dec 31	152.7, 153.25, 152.6, 152.7	2758	2166	3190
Jan 31	152.95, 153.45, 152.8, 152.85	68	65	144
Nickel MCX(1 K)				
Dec 31	987.2, 996.5, 985.4, 994	9372	5589	2896.5
Jan 31	984.7, 993.1, 984.7, 991.9	97.5	62	195
Zinc MCX(1 K)				
Dec 31	183.2, 184.5, 183.05, 183.6	26930	4474	16325
Zinc Mini MCX(1 K)				
Dec 31	183.3, 184.9, 183.3, 183.8	9002	6784	5251
Jan 31	183.05, 183.75, 182.85, 183.05	725	456	1727
Feb 28	183.45, 183.5, 183.45, 183.5	2	2	5
Metal- precious				
Gold MCX(10 G)				
Feb 05	38011, 38080, 37958, 38011	3.63	3117	17.4
Apr 03	38065, 38128, 38015, 38050	0.06	56	1.94
Gold Guinea MCX(8 G)				
Dec 31	30569, 30588, 30527, 30569	0	100	0
Jan 31	30560, 30580, 30546, 30574	0	27	0
Gold Mini MCX(10 G)				
Jan 03	38087, 38126, 38005, 38064	0.47	3920	0.88
Feb 05	38047, 38099, 37980, 38033	0.09	743	0.24
Gold Petal MCX(1 Gm)				
Dec 31	3885, 3902, 3872, 3879	0	474	0.01
Jan 31	3862, 3869, 3851, 3861	0	125	0
Silver MCX(1 K)				
Mar 05	44599, 44599, 44328, 44461	166.38	4729	378.6
May 05	44959, 45059, 44902, 45004	0.42	14	5.67
Silver Micro MCX(1 K)				
Feb 28	44596, 44596, 44371, 44498	15.91	10787	29.83
Apr 30	45105, 45105, 44879, 45040	0.47	385	1.18
Jun 30	45947, 45947, 45947, 45947	0	1	0.01
Silver Mini MCX(1 K)				
Feb 28	44556, 44597, 44363, 44486	49.13	7758	57.05
Apr 30	45081, 45087, 44896, 45034	0.51	100	0.99
Jun 30	46665, 46665, 46665, 46665	0.01	1	0.02

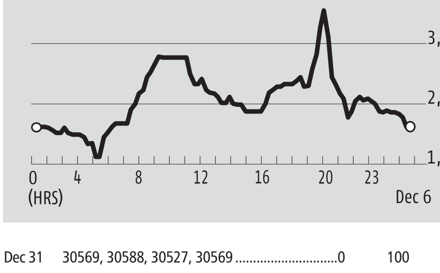

तेल एवं गैस

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Gas				
Natural Gas MCX(1 MB)				
Dec 26	173.5, 174.1, 171.3, 173.5	49571mb	21519	30720mb
Jan 28	171.9, 173, 170.6, 172.6	3145mb	1836	8600mb
Feb 25	167.1, 168.1, 166, 167.5	353mb	255	2021mb
Oil				
Crude Oil MCX(1 BL)				
Dec 18	4159, 4178, 4147, 4159	6179bl	32159	2975bl
Jan 17	4166, 4181, 4148, 4164	150bl	1093	189bl
Crude Oil Mumbai MCX(1 Bl)				
Dec 18	4162, 4177, 4147, 4159	1347bl	56304	660bl

सायं सत्र (गुरुवार)

कृषि जिंस

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Cotton				
Cotton MCX(1 B)				
Dec 31	19100, 19150, 19020, 19050	2645	372	9014
Jan 31	19210, 19290, 19180, 19210	315	59	2483
Kapas MCX(20 K)				
Apr 30	1066.5, 1073, 1066.5, 1072	120	28	612
Shankar Kapas-Rajkot NCDEX(20 Kg)				
Apr 30	1068, 1073, 1065, 1070	871	412	3821
Oil and Oilseeds				
Crude Palm Oil MCX(10 K)				
Dec 31	689.4, 697, 687, 696.3	19500	1340	42340
Jan 31	690, 695.4, 686.8, 694.4	8420	632	19380
Feb 28	694.5, 698.4, 690.5, 696.5	2410	193	2300
Ref Soy Oil-IDR-2016 NCDEX(10 Kg)				
Dec 20	828.4, 842, 826.2, 840.2	19150	1711	22335
Jan 20	830, 838.2, 826.2, 837.4	21580	2161	48205
Feb 20	827.2, 833, 823.4, 832.6	4470	311	15290
Mar 20	827, 829.2, 826.2, 827.4	25	4	35

धातु

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Metal- non ferrous				
Aluminium MCX(1 K)				
Dec 31	133.1, 133.45, 132.4, 132.6	8610	1303	8955
Aluminium Mini MCX(1 K)				
Dec 31	133.15, 133.5, 132.4, 132.6	3969	3099	3014
Jan 31	134.3, 134.3, 133.55, 133.7	181	147	246
Copper MCX(1 K)				
Dec 31	430.85, 432.4, 429.8, 430.6	26667.5	8869	14750
Jan 31	435.7, 436.95, 434.8, 435.25	295	116	835
Lead MCX(1 K)				
Dec 31	152.95, 153.45, 152.4, 152.6	15845	2663	6160
Lead Mini MCX(1 K)				
Dec 31	153.1, 153.4, 152.5, 152.6	6266	5169	2765
Jan 31	153.25, 153.5, 152.8, 152.9	137	129	133
Nickel MCX(1 K)				
Dec 31	972.5, 997.3, 965.8, 983.6	24628.5	14786	2287.5
Jan 31	972.5, 994, 965.8, 982.2	372	244	199.5
Feb 28	978.5, 978.5, 978.5, 978.5	1.5	1	1.5
Zinc MCX(1 K)				
Dec 31	183.75, 184.95, 182.1, 182.75	54035	8704	14730
Zinc Mini MCX(1 K)				
Dec 31	184.4, 185.15, 182.55, 183.05	19170	14594	4807
Jan 31	183.8, 184.75, 182, 182.6	1033	755	1486
Feb 28	184.5, 184.5, 183, 183.75	6	6	4
Metal- precious				
Gold MCX(10 G)				
Dec 05	38850, 38850, 38192, 38089	0.01	12	0.08
Feb 05	38149, 38237, 37952, 38085	10.47	8971	16.81
Apr 03	38182, 38260, 38017, 38119	0.13	126	1.9
Gold Guinea MCX(8 G)				
Dec 31	30570, 30687, 30520, 30569	0	436	0
Jan 31	30630, 30672, 30590, 30615	0	31	0
Gold Mini MCX(10 G)				
Dec 05	38245, 38245, 37800, 38089	0	13	0
Jan 03	38176, 38270, 38010, 38131	1.37	11526	0.78
Feb 05	38142, 38249, 37982, 38107	0.24	2004	0.22
Gold Petal MCX(1 Gm)				
Dec 31	3885, 3898, 3871, 3879	0.01	1594	0.01
Jan 31	3858, 3874, 3858, 3865	0	234	0
Silver MCX(1 K)				
Dec 05	44200, 45287, 43850, 44333	1.32	28	1.32
Mar 05	44525, 44688, 44270, 44610	542.1	14838	353.61
May 05	45102, 45183, 44805, 45009	1.59	53	5.49
Silver Micro MCX(1 K)				
Feb 28	44510, 44712, 44222, 44630	58.98	39125	26.02
Apr 30	45134, 45225, 44835, 45145	1.25	1029	1.1
Jun 30	46299, 46299, 46299, 46299	0	1	0.01
Silver Mini MCX(1 K)				
Feb 28	44543, 44713, 44255, 44634	179.41	27872	48.1
Apr 30	45110, 45233, 44840, 45153	1.77	327	0.89

तेल एवं गैस

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Gas				
Natural Gas MCX(1 MB)				
Dec 26	172.6, 176, 170.3, 174.6	154558mb	70317	25770mb
Jan 28	171, 174.6, 170, 173.3	12673mb	6422	8346mb
Feb 25	166.8, 169, 165.3, 168.3	976mb	722	1940mb
Oil				
Crude Oil MCX(1 BL)				
Dec 18	4167, 4215, 4140, 4161	32054bl	153539	1925bl
Jan 17	4167, 4220, 4145, 4167	818bl	6636	170bl
Feb 19	4210, 4210, 4210, 4210	0bl	2	0bl
Crude Oil Mumbai MCX(1 Bl)				
Dec 18	4179, 4217, 4132, 4161	7239bl	275172	454bl

g-grams, k-kilograms, q-quintals, t-tonnes, b-bales,bl-barels,mb-mmBTU,m-Mnd; Quantity & Open interest in tonnes except for crude oil and natural gas; For Gas is '000 mmBTU & for crudeoil in '000 barrel; Market price in ₹.

राजकोषीय नीति का करें विस्तार: बिड़ला

कुमार मंगलम बिड़ला ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर में कटौती समेत राजकोषीय प्रोत्साहनों की दरकार

इंदिवजल धस्माना

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) और आदित्य बिड़ला समूह के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला ने विस्तारित राजकोषीय नीति को अपनाए जाने की बात कही ताकि अर्थव्यवस्था को मंदी के दलदल से बाहर निकाला जा सके। विस्तारित राजकोषीय नीति ऐसी राजकोषीय नीति है, जिसमें मंदी के दबाव को दूर करने के लिए करों को घटाने या सरकारी व्यय को बढ़ाने या दोनों ही उपयों को अपनाया जाता है।

राजस्व सचिव ए बी पांडे के साथ बजट से पहले की चर्चा के दौरान सीआईआई के एक प्रतिनिधि मंडल ने राजकोषीय घाटे को लक्ष्य की तुलना में 0.5–0.75 फीसदी अंक बढ़ाने का सुझाव दिया। इससे सरकार को करीब 1.1 लाख करोड़ रुपये से 1.6 लाख करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त राजकोषीय गुंजाइश मिलेगी।

सीआईआई ने कहा कि इस अतिरिक्त राजकोषीय गुंजाइश का इस्तेमाल पूंजीगत व्यय विशेष रूप से बुनियादी ढांचे में निवेश में किया जाना चाहिए। सीआईआई ने कहा कि राजकोषीय जिम्मेदारी एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) समिति द्वारा दिए गए लक्ष्यों पर दो–तीन साल की अवधि में लौटने का एक रास्ता होना चाहिए।

एक अलग कार्यक्रम में बिड़ला ने कहा कि सरकार को कॉरपोरेट टैक्स की दर में कटौती से अधिक प्रयास करने और वस्तु एवं सेवा कर की दरों में कटौती समेत अर्थव्यवस्था को मजबूत राजकोषीय प्रोत्साहन मुहैया कराने की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि राजकोषीय मितव्ययिता कारोबार में दिखाई जानी चाहिए, लेकिन मंदी के साल में इसके असर को मात देने के लिए राजकोषीय नीति की भी जरूरत होती है।

बिड़ला ने कहा, 'मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं, लेकिन मेरा मानना है कि अब स्थितियों में सुधार आएगा। मुझे नहीं लगता कि बड़ी कंपनियों को ऋण में बहुत जल्द तेजी आएगी। ज्यादातर की बैलेंस शीट में अब भी भारी कर्ज है। मुझे लगता है कि उन्हें इसे कम करना चाहिए। मेरा यह भी मानना है कि सरकार को अर्थव्यवस्था को तगड़ा राजकोषीय प्रोत्साहन देना चाहिए। एफआरबीएम अधिनियम आधा फीसदी कम–अधिक होने की छूट देता है।'

- विस्तारित राजकोषीय नीति में मंदी दूर करने के लिए कर कटौती व राजकोषीय व्यय बढ़ाने जैसे कदम उठाए जाते हैं
- बजट पूर्व चर्चा में सीआईआई प्रतिनिधिमंडल ने राजकोषीय घाटा **0.5-0.75** फीसदी बढ़ाने का दिया सुझाव
- इससे सरकार के राजकोष में होगी **1.1** से **1.6** लाख करोड़ रुपये तक की वृद्धि

केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा अक्टूबर तक ही वित्त वर्ष 2020 के बजट लक्ष्य 7.04 लाख करोड़ रुपये को पार कर चुका है। बजट में अनुमान जताया गया है कि वित्त वर्ष 2020 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.3 फीसदी रहेगा। बजट के साथ पेश किए गए राजकोषीय रूपरेखा पत्रों में अनुमान जताया गया है कि वित्त वर्ष 2021 और वित्त वर्ष 2022 में राजकोषीय घाटा तीन फीसदी रहेगा।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कमजोर घरेलू और विदेशी मांग को मद्देनजर रखते हुए गुरुवार को चालू वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि का अनुमान घटाकर 5 फीसदी कर दिया, जो पहले 6.1 फीसदी था। सरकार ने 20 सितंबर को कॉरपोरेट टैक्स की दर 30 फीसदी से घटाकर 22 फीसदी करने की घोषणा की थी। यह कटौती उन कंपनियों के लिए की गई थी, जो किसी तरह की छूट नहीं लेती हैं। इसके अलावा कुछ नई विनिर्माण कंपनियों के लिए कर की दर 25 फीसदी से घटाकर 15 फीसदी की गई थी।

अधिभार और उपकर (विशेष उद्देश्यों के लिए धन जुटाने के लिए लगाए जाने वाले शुल्क) समेत कॉरपोरेट टैक्स की प्रभावी दर करीब 10 फीसदी घटकर 25.2 फीसदी पर आ गई है।

सरकार ने सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज करने के लिए कॉरपोरेट कर में कटौती के अलावा अन्य कदम भी उठाए हैं। इनमें लालफीताशाही को कम करने और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को बढ़ाने के प्रयास और सरकारी बैंकों को मजबूत बनाने की योजना शामिल हैं। बिड़ला ने कहा, 'कर में कटौती का हमेशा स्वागत है। अगर सरकार हमें और कर छूट देने का फैसला करती है तो वह सबसे ज्यादा अच्छा होगा। इससे हमारी नकद आवक बढ़ती है और हमें वृद्धि करने की ज्यादा गुंजाइश देती है। सरकार ने काफी काम किया है। मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं। सरकार को जो काम करने चाहिए, उनमें से एक यह है कि तगड़ा राजकोषीय प्रोत्साहन दिया जाए।'

उन्होंने कहा कि कुछ कॉरपोरेट पैकेज का इस्तेमाल कर्ज चुकाने में करना चाहेंगे और कुछ इसका उपयोग क्षमता विस्तार में करना पसंद करेंगे। बिड़ला ने इस बात से इत्तेफाक नहीं जताया कि आयकर की दर में कटौती के जरिये उपभोक्ता खर्च को बढ़ाने से अर्थव्यवस्था को मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा, 'हम खपत के जरिये मंदी से बाहर नहीं आ सकते क्योंकि इस समय लोग कम आमदनी की वजह से ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते हैं। देश में बेरोजगारी है। इसका सबसे अच्छा तरीका राजकोषीय प्रोत्साहन है। अगर जीएसटी की दर घटाकर 15 फीसदी पर लाई जाती है तो यह बड़ा प्रोत्साहन होगा।'

बैंक कर्मियों के संरक्षण की व्यवस्था

पृष्ठ 1 का शेष

उन्होंने कहा कि सरकार का विशेष जोर देश के सबसे अधिक पिछड़े 112 जिलों पर है जो विकास के हर पैमाने पर पिछड़ गए हैं। इसे दुरुस्त करने के लिए हर सप्ताह सैकड़ों कर्मचारियों को वहां भेजा जा रहा है ताकि उन्हें विकास की दौड़ में बाकी देश के साथ लाया जा सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने सस्ते मकान बनाने, 15 करोड़ घरों तक नल से पानी पहुंचाने और पर्यटन के जरिये रोजगार पैदा करने की दिशा में कदम उठाए हैं। व्यक्तिगत करों में कटौती से लोगों के पास पैसा आएगा जिससे निवेश और विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। श्रम कानूनों में बदलाव और पुराने कानूनों को व्यावहारिक बनाने से कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि सरकार विनिवेश की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है।

मोदी ने कहा कि पिछले साल कारोबारी सुगमता सूचकांक में भारत की प्रगति पर बधाई देने के लिए विश्व बैंक के प्रमुख ने उन्हें फोन किया था। उन्होंने कहा, 'मेरी सरकार वादों की नहीं बल्कि काम करके दिखाने की राजनीति कर रही है। पहले रेल लाइनों की घोषणा कर भुला दी जाती थीं, ऋण माफी के सिर्फ वादे होते थे। सड़क परियोजनाओं की घोषणा होती थी, लेकिन जल्द ही कागजों से गायब हो जाती थीं। मेरी सरकार हर वादे को पूरा करने की कोशिश कर रही है।'

उन्होंने बैंकिंग क्षेत्र को लेकर कहा कि 'इसी कमरे में आपमें से बहुत से लोगों' ने सिफारिश की थी कि भारत को ज्यादा बैंकों की नहीं बल्कि मजबूत बैंकों की जरूरत है। सरकार इसी दिशा में कदम बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार ने बैंकों में नई पूंजी डालने की प्रतिबद्धता जताई। रियल एस्टेट क्षेत्र को स्पेशल विंडो मुहैया कराई गई है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने अफसरशाही को इस ढंग से पुनर्गठित करने की योजना बनाई है कि भारत की प्रगति के लिए प्रतिबद्ध अफसरों पर कैडर या सेवाओं के जरिये पीछे नहीं धकेला जाए। जिन अफसरों पर आरोप होंगे, उन्हें सेवा से मुक्त होने के लिए कहा जाएगा। कर संग्रह में डिजिटलीकरण और तकनीक के इस्तेमाल से कर आकलन में करदाता और अधिकारी को आमने–सामने पेश होने की जरूरत नहीं है। ताकतवर कर अधिकारियों द्वारा खड़ा किया गया स्थानांतरण उद्योग गुजरे जमाने की बात हो चुका है। उन्होने कहा, 'अब कर आकलन में कोई खेल नहीं होगा।'

जेफरीज में इक्विटी रणनीति के वैश्विक प्रमुख क्रिस्टोफर वुड

'अर्थव्यवस्था मोदी सरकार के झटकों की शिकार'

वुड का अनुमान है कि सरकार अर्थव्यवस्था को सुधारने के उपाय जारी रखेगी

पुनीत वाधवा

भारतीय अर्थव्यवस्था नरेंद्र मोदी सरकार के शॉक थैरेपी (झटकों) की शिकार है और जोखिम न लेने वाले निवेशक यह मान सकते हैं कि अर्थव्यवस्था को उबरने में चार तिमाही लग सकती हैं और अगर पहले सुधार आता है तो यह उनके लिए अचंभा होगा। जेफरीज में इक्विटी रणनीति के वैश्विक प्रमुख क्रिस्टोफर वुड ने निवेशकों को अपने साप्ताहिक नोट ग्रीड ऐंड फीयर में यह लिखा है।

हालांकि उन्होंने अनुमान जताया है कि नोटबंदी, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), रियल एस्टेट रेग्यूलेशन एक्ट (रेरा) और दिवालिया संहिता जैसे कानून लंबी अवधि में सकारात्मक साबित होंगे। वुड ने कहा, 'इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन सुधारों के शुरुआती झटके के असर को भाजपा सरकार ने कम करके आंका। असल में भारतीय अर्थव्यवस्था और उसके उद्यमी वर्गों की तुलना पहले के उस नशेड़ी से की जा सकती है, जिसे अचानक नशा बंद कर दिया है। अब सरकार नशा छोड़ने के होने वाले लक्षणों पर बहुत अधिक ध्यान दे रही है।'

वुड ने लिखा, 'महंगाई लगातार कमजोर बने रहने से आर्थिक सुस्ती नॉमिनल जीडीपी के लिहाज से ज्यादा नाटकीय नजर आ रही है। वर्ष 2019 की तीसरी तिमाही में नॉमिनल जीडीपी की वृद्धि सालाना आधार पर महज 6.1 फीसदी रही, जो वर्ष 2009 की पहली तिमाही से सबसे सुस्त वृद्धि है। भारतीय अर्थव्यवस्था एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनैंस कंपनी क्षेत्र में कम ऋण वितरण के असर से लगातार प्रभावित हो रही है।' इस पृष्ठभूमि में वुड का मानना है कि सरकार अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए आगे भी उपायों की घोषणा करती रहेगी, लेकिन वह बढ़त राजकोषीय घाटे को लेकर भी फिक्रमंद है। वुड का मानना है कि बढ़ते राजकोषीय घाटे की वजह से ही सरकार भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) समेत सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के विनिवेश की योजनाओं को तेज कर रही है। वुड ने कहा, 'सरकार 1 फरवरी को पेश किए जाने वाले वाले बजट में निस्संदेह और मददगार उपायों की घोषणा करेगी। लेकिन आयकर दर में कटौती के आसार कम हैं।'

मिड और स्मॉल कैप को नुकसान

वुड का मानना है कि आर्थिक मंदी का असर लार्ज कैप की तुलना में मिड और स्मॉल कैप शेयरों पर ज्यादा पड़ा है। मिड कैप और स्मॉल कैप सूचकांक जनवरी 2018 के अपने अब तक के सर्वोच्च स्तर से क्रमश: 40 फीसदी व 22 फीसदी नीचे हैं। इस साल अब तक विदेशी निवेशक भारतीय इक्विटी के शुद्ध खरीदार रहे हैं। उन्होंने 2019 में अब तक 13.2 अरब डॉलर की शुद्ध लिवाली की है, जबकि 2018 में 4.6 अरब डॉलर की शुद्ध बिकवाली की है।

आर्थिक मंदी से ट्रक बॉडी बनाने वाले छोटे कारीगर बेहाल

अभिषेक वाघमारे

जीएसटी आने से भी ट्रक की बॉडी बनाने वाले काम में आई मुश्किलें

नरमी का असर

दिल्ली–उत्तर प्रदेश बॉर्डर के पास अब्दुल कादिर की ट्रक बॉडी बनाने वाली वर्कशॉप में एक मैली सी डेस्क और करीब 10,000 रुपये की कीमत वाला कोरयो टेलीविजन रखा हुआ है। हालांकि उन्हें सैमसंग के टीवी पसंद हैं लेकिन कारोबार में मंदी ने उन्हें लागत में कटौती को मजबूर किया जिसके चलते कादिर ने टेलीविजन के सस्ते ब्रांड को चुना। ट्रक का केबिन बनाने वाले एक कारीगर रवि जो कादिर को भी अपनी सेवाएं देते हैं, यह देखने आए हैं कि क्या किसी नए काम का ऑर्डर आया है? रवि ट्रक का एक केबिन बनाने के लिए 4,500 रुपये लेते हैं और पिछले साल तक वह एक महीने में पांच ट्रक तैयार कर लेते थे। इन दिनों वे एक महीने से दिहाड़ी आधार पर एक ही केबिन को बना रहे हैं।

39 वर्षीय कादिर कहते हैं, 'मेरे 25 साल के कारोबार में मैंने कभी भी मांग में इतनी गिरावट नहीं देखी। पिछली गर्मियों में पूरा यार्ड नए वाणिज्यिक वाहनों से भरा हुआ था और इस बार हमारे पास केवल एक ट्रक है।' कादिर स्कूल से पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने पिता के कारोबार में हाथ बंटाने लगे थे।

कादिर जिस मंदी का सामना कर रहे हैं वह वाणिज्यिक वाहनों, विशेषकर मीडियम और भारी वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री में आई गिरावट से प्रत्यक्ष तौर पर जुड़ी है। इस श्रेणी के वाणिज्यिक वाहन पूरी बॉडी के साथ नहीं आते और इसलिए इनकी बॉडी को बाहर बनवाना होता है। हालांकि सितंबर एवं अक्टूबर महीने में इन श्रेणी के वाहनों की बिक्री में 50 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट आई है जबकि इनके पंजीकरण में 20 प्रतिशत की कमी देखी गई।

इसके चलते वाणिज्यिक वाहनों से जुड़ी आगे की सभी कड़ियां गंभीर आर्थिक तनाव से गुजर रही हैं जिसमें इस तरह की इकाइयों में काम कर रहे हजारों असंगठित श्रमिक शामिल हैं। भारत में मझोले एवं भारी वाणिज्यिक वाहन बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी टाटा मोटर्स का कहना है कि कंपनी द्वारा बनाए जाने वाले वाहनों में से करीब 90 प्रतिशत पूरी तरह से कंपनी में ही बनाए जाते हैं। मंदी से प्रभावित ट्रॉसपोर्ट कंपनियां भी लागत में कटौती कर रही हैं। अग्रवाल पैकर्स ऐंड मूवर्स के उपाध्यक्ष (उत्तर भारत) एच पी सिंह कहते हैं, 'हमारे ट्रक लागत की भी भरपाई नहीं कर पा रहे हैं। हमें छंटनी करनी पड़ रही है। नए ट्रकों को बेड़े में शामिल करने को तो भूल ही जाइए, अब हमें कर्ज लेकर खरीदे ट्रकों का ब्याज चुकाने में ही मुश्किल हो रही है।' कादिर कहते हैं, 'ट्रक मालिक हमारे यार्ड में ट्रक खड़े करते थे। साल 2018 तक वे हमसे वरीयता के आधार पर काम करने का निवेदन करते थे। लेकिन अब वे अपने ऑर्डर वापस ले रहे हैं और ट्रॉसपोर्ट के काम में तेजी आने तक चेसिस बिना बना हुआ ही छोड़ रहे हैं।' जब बात कर्मियों की आती है तो यह तकलीफ दोगुनी हो जाती है। पिछले वर्ष कादिर ने अपने यार्ड में 30 से अधिक श्रमिकों को काम दिया था। आज, उनके साथ केवल चार कर्मी हैं और उनके पास भी करने के लिए कोई अधिक काम नहीं है। एक कर्मी बिहार में अपने घर वापस लौट गया है जिससे वह खाने और किराए की लागत को बचा सके।

कादिर ने उन्हें 5,000 रुपये उधार दिए हैं जिसे भविष्य में किसी काम के बदले चुका लिया जाएगा। हालांकि रवि फिलहाल टिके हुए हैं। वह कहते हैं, 'वेल्डिंग, पेंटिंग वाले मिल जाते हैं। केबिन बनाना स्पेशलिस्ट काम होता है।'

ट्रक बॉडी बनाने वाले दूसरे कारीगरों ने नाम सार्वजनिक नहीं करने की शर्त पर बताया कि फिरसे गैरकानूनी गतिविधियां बढ़ रही हैं। जैसे, एजेंट स्थानीय परिवहन कार्यालय से पूरी बॉडी वाले वाणिज्यिक वाहनों के पंजीकरण संबंधी कागजात ले रहे हैं। इसके अलावा ट्रॉसपोर्ट कारोबार में लागत बढ़ रही है, जिसके चलते कमजोर मांग के चलते ट्रॉसपोर्ट बिल बदलने की प्रवृत्ति देखी जा रही है। डीजल की बढ़ती कीमतें भी एक कारक हैं।

हैदराबाद मामले पर मिली–जुली प्रतिक्रिया

हैदराबाद में पशुचिकित्सक के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या करने के चारों आरोपियों के शुक्रवार को कथित पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने की घटना की राजनेताओं ने जहां एक ओर प्रशंसा की वहीं उनमें इसके प्रति चिंता भी देखी गई। जया बच्चन सहित कई नेताओं ने इसे दुष्कर्म पीड़िता के लिए त्वरित न्याय करार दिया, वहीं मेनका गांधी और शशि थरूर ने कहा कि न्याएतर हत्या चिंता का विषय है।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा कि तथ्यों का पता लगाने के लिए जांच की जरूरत है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने पत्रकारों से कहा, 'मुझे हैदराबाद में हुई घटना से संबंधित तथ्यों की जानकारी नहीं है। बस मैं यही कह सकता हूं कि इस बात की गहन जांच करने की जरूरत है कि क्या मुठभेड़ वास्तविक थी, क्या वे भागने की कोशिश कर रहे थे या कुछ और था।' उल्लेखनीय है कि 25 वर्षीय पशुचिकित्सक से पिछले महीने दुष्कर्म के चारों आरोपी शुक्रवार सुबह पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में मारे गए।

घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए सपा की राज्यसभा सदस्य जया बच्चन ने कहा बहुत देर कर दी। देर आए दुरुस्त आए। भाजपा नेता मेनका गांधी ने कहा, 'यह देश के लिए भयानक नजीर है।' उन्होंने कहा, 'जो भी हुआ, बहुत भयानक हुआ है इस देश के लिए...आप लोगों को इसलिए नहीं मार सकते क्योंकि आप ऐसा करना चाहते हैं। आप कानून को अपने हाथ में नहीं सकते हैं, उन्हें (आरोपियों को) अदालत से तो फांसी मिलने ही वाली थी।' मेनका ने कहा, 'फिर फायदा क्या है? फायदा क्या है अदालत का, फायदा क्या है पुलिस का? तब तो जिस को चाहो उठाओ और गोली मार दो।' *भाषा*